सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 364, नई दिल्ली । बुधवार, 13 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो ।

03 दिल्ली की बकाया 2 सीट से कौन होगा उम्मीदवार ?
06 एमएसपी को कानूनी दर्जे से मजबूत होगी कृषि
08 जिला कलक्टर ने ली विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक

दिल्ली परिवहन विभाग की व्यवसायिक वाहन से सम्बंधित आटो शाखा, एमएलओ (एच.क्यू.), में वाहन मालिक परेशान, कोन है जिम्मेदार !!

संजय बाटला

नई दिल्ली । दिल्ली परिवहन विभाग में निम्न श्रेणी के पदो के कर्मचारियों की काफी वर्षों से कमी चली आ रही है और इसी के हल के लिए पूर्व विशेष परिवहन आयुक्त के.के. दहिया द्वारा परिवहन विभाग में डाटा ऑपरेटर्स को कांट्रेक्ट पर लेकर विभाग की सभी शाखाओं में कार्यों पर लगाकर जनहित के प्रति एक बड़ा कदम उठाया था पर आज उनके रिटायर होने के बाद आए विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम को डाटा ऑपरेटर्स द्वारा मुख्य रूप से जिन शाखाओं में इनकी (डाटा एंट्री ऑपरेटर्स) सब से ज़्यादा आवश्यकता है में कार्य पर होना गलत माना गया है जब की यही डाटा एंट्री ऑपरेटर्स दिल्ली में सभी शाखाओं में मुख्य कार्यों पर कार्य में लगाए हुए है । जी हां इसका सबूत है उनके द्वारा जारी आदेश, जब की इस आदेश के कुछ ही दिनों पहले उन्ही के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर को इन्ही शाखाओं में कार्य करने के लिए ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए थे और एक साथ एक ही शाखा में 3 डाटा ऑपरेटर्स को कार्य करने के लिए भेजा था पर कुछ ही समय में अपना विचार बदल कर और बिना अन्य किसी कर्मचारी को उनकी जगह पर कार्य करने के लिए भेजे तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश एक सवाल उठाता है । क्योंकि आटो टेक्सी शाखा, एमएलओ (एच. क्यू.), वीआईयू बुराड़ी और एसटीए शाखा में कर्मचारियों के ना होने और इस तुगलकी आदेश के कारण व्यवसायिक वाहन मालिक बहुत परेशान हैं । यहां तक की नया व्यासायिक वाहन खरीद कर पंजीकरण के लिए विभाग में पेपर जमा करवा चुके वाहन मालिकों को वाहन के पंजीकरण नही हो पाने से जुर्माने के साथ बैंको की किश्तों का भी बिना वाहन चलाए भरने के चिंताओं में भर दिया है । आटो के लिए जनहित में लगी कई संस्थाओं के सदस्य इस परेशानी को लेकर पिछले हफ्ते विशेष परिवहन आयुक्त से मुलाकात करके भी गए थे और उन्होंने बताया था की अब तक 2500 से उपर एप्लीकेशन पेंडिंग हो चुकी है जो अब तक 3000 से अधिक हो चुकी है अब बताएं कोन है व्यवसायिक वाहन मालिको को जान बुझकर कर परेशानी मे डलवाने वाला ? और कानून के अंतर्गत ऐसे अधिकारी के लिए क्या सजा बनती है ? क्योंकि अगर यही गलती शाखा में कार्यरत कर्मचारी / अधिकारी द्वारा किया गया पाया जाता हैं तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता हैं पर क्या यह नियम विभाग के आला अधिकारी पर भी लागू होता है यह सबसे बड़ा सवाल है ?

कृप्या करके उपराज्यपाल दिल्ली, मुख्य सचिव दिल्ली, आयुक्त परिवहन विभाग, मुख्यमंत्री एवम्‌परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार तत्काल जनता को जान बुझकर परेशान करने वाले के खिलाफ नियम/ कानून के अंतर्गत कार्यवाही और जनता को परेशानी से छुटकारा दिलवाने के लिए तत्काल प्रभाव से सभी शाखाओं जहा से अन्य कर्मचारी भेजे बिना डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हटाए गए हैं को कर्मचारी / डाटा ऑपरेटर्स प्रदान करवाए जाएं ।

आदेश की कापी आपकी जानकारी हेतु

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार परिवहन विभागः प्रशासन शाखा 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054 (वेबसाइटः http://www.trasnport.delhigovt.nic.in)

एफ.नं.
9/2/प्रशा./टीपीटी./2006/पीटी.फ़ाइल/07 5613897//4744

आदेश
दिनांकः-01.3.2.24

डीईओ जो वर्तमान में विभाग में पूरी तरह से संविदा पर कार्यरत हैं । देखा गया है कि डीईओ को संवेदनशील शाखा में भी पदस्थापित किया जाता है । आदेश दिया जाए कि संवेदनशील शाखा ले में किसी भी डीईओ की पोस्टिंग न की जाए । डीटीओ (मुख्यालय), वीआईयू, एसटीए शाखा, और एआरयू शाखा ।

प्रशासन शाखा यह सुनिश्चित करेगी । डीटीओ भी इसे सुनिश्चित करेंगे और इन शाखाओं में तैनात किसी भी डीईओ को तुरंत कार्यमुक्त किया जाएगा ।

विशेष आयुक्त (प्रशासन) परिवहन विभाग

एफ.नं.
9/2/प्रशा./टीपीटी./2006/पीटी.फ़ाइल/07 5613897/14744

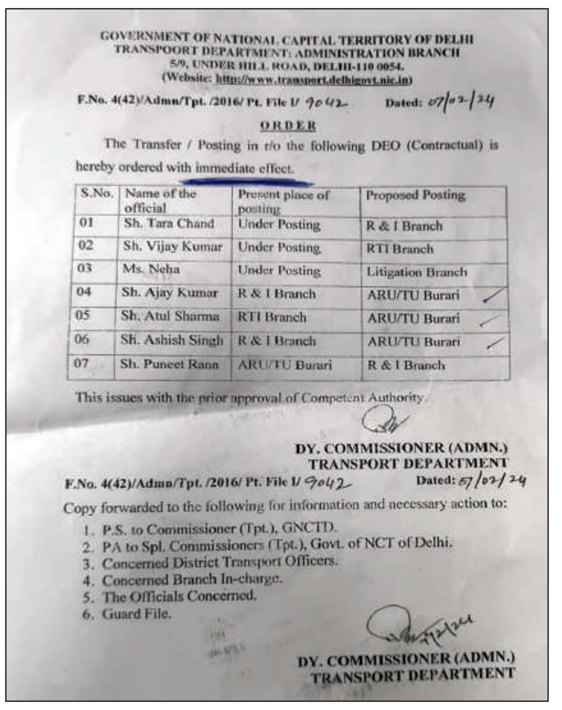

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPOORT DEPARTMENT: ADMINISTRATION BRANCH
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-110 0054.
(Website: http://www.transport.delhigovt.nic.in)

F.No. 4(42)/Admn/Tpt. /2016/ Pt. File I/ 9042 Dated: 07/02/24

ORDER

The Transfer / Posting in r/o the following DEO (Contractual) is hereby ordered with immediate effect.

S.No.	Name of the official	Present place of posting	Proposed Posting
01	Sh. Tara Chand	Under Posting	R & I Branch
02	Sh. Vijay Kumar	Under Posting	RTI Branch
03	Ms. Neha	Under Posting	Litigation Branch
04	Sh. Ajay Kumar	R & I Branch	ARU/TU Burari
05	Sh. Atul Sharma	RTI Branch	ARU/TU Burari
06	Sh. Ashish Singh	R & I Branch	ARU/TU Burari
07	Sh. Puneet Rana	ARU/TU Burari	R & I Branch

This issues with the prior approval of Competent Authority.

DY. COMMISSIONER (ADMN.)
TRANSPORT DEPARTMENT

F.No. 4(42)/Admn/Tpt. /2016/ Pt. File I/ 9042 Dated: 07/02/24

Copy forwarded to the following for information and necessary action to:
1. P.S. to Commissioner (Tpt.), GNCTD.
2. PA to Spl. Commissioners (Tpt.), Govt. of NCT of Delhi.
3. Concerned District Transport Officers.
4. Concerned Branch In-charge.
5. The Officials Concerned.
6. Guard File.

DY. COMMISSIONER (ADMN.)
TRANSPORT DEPARTMENT

में कॉपीः
1. पी.एस. सचिव सह-आयुक्त (टीपीटी), जीएनसीटीडी ।
दिनांकः-01-3.224
2. पीए से स्प्ल. आयुक्त (टीपीटी), सरकार टी. दिल्ली के एनसीटी के.
3. संबंधित डीटीओ को उपरोक्त आदेश के अनुपालन के निर्देश के साथ और उनकी शाखा में तैनात किसी भी डीईओ (संविदा) को प्रशासन को रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ तुरंत कार्यमुक्त किया जाए । आगे की पोस्टिंग के लिए शाखा, परिवहन (मुख्यालय) ।
4. संबंधित अधिकारी.
5. गार्ड फ़ाइल.

पीएम ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर जनऔषधि केंद्र का शुभारंभ किया, इन स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे स्थानीय उत्पाद

पीएम मोदी ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र और सांबा में गति शक्ति टर्मिनल का उद्घाटन किया।

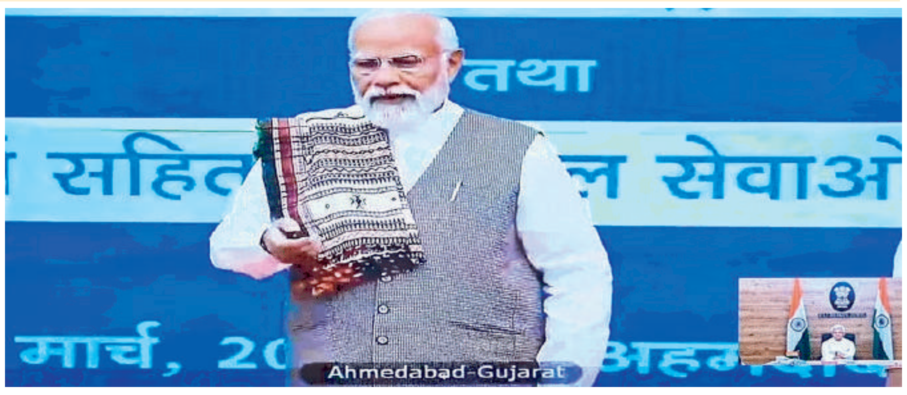

परिवहन विशेष न्यूज

जम्मू । उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में रेल बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार लाने और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को कई रेलवे परियोजनाएं समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 85,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया ।

पीएम मोदी ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र और सांबा में गति शक्ति टर्मिनल का उद्घाटन किया । साथ ही प्रधानमंत्री ने अनंतनाग, अवंतीपोरा, बनिहाल, बारामुला, बडगाम, जम्मू, काजीगुंड, कटड़ा, श्रीनगर, बिजबेहड़ा, कठुआ, पंपोर, पट्टन, काकापोरा, पंजगाम, सदूर में 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (ओएसओपी) स्टॉल भी जनता को समर्पित किए । साथ ही मझोम रेलवे स्टेशन और श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्तरां का लोकार्पण किया ।

उपराज्यपाल ने कहा कि श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के खुलने से यात्रियों को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और कई लोगों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित होंगे । प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर शुरू किए गए 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (ओएसओपी) के स्टॉल सीमांत वर्गों के कारीगरों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करेंगे । ओएसओपी इन क्षेत्रों की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देगा और यह 'वोकल फॉर लोकल' और 'एक जिला एक उत्पाद अभियान' को भी मजबूत करेगा । ये स्टॉल यात्रियों को प्रामाणिक स्थानीय वस्तुओं का अनुभव करने और खरीदने का अवसर प्रदान करेंगे ।

माननीय प्रधान मंत्री ने सांबा में गति शक्ति टर्मिनल और श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्तरां का भी उपहार दिया है । गति शक्ति टर्मिनल पूरे क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने और सामान की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।

एनएच-913 के आठ खंडों का होगा निर्माण, सड़क मंत्रालय ने मंजूर किए

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नेशनल हाईवे-913, जिसे फ्रंटियर हाइवे कहा जाता है, पर आठ हिस्सों के निर्माण के लिए 6,621.62 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नेशनल हाईवे-913, जिसे फ्रंटियर हाइवे कहा जाता है, पर आठ हिस्सों के निर्माण के लिए 6,621.62 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं ।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया X पर एक श्रृंखला में पोस्ट करते हुए कहा कि यह व्यापक परियोजना कुल 265.49 किलोमीटर लंबी है ।

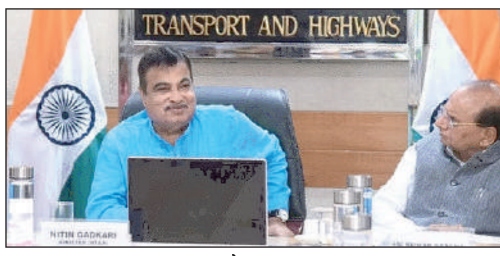

गडकरी ने कहा कि इस पहल में पैकेज 1, 3 और 5 शामिल हैं, जो हुरी-तलीहा खंड को कवर करते हैं । बाइल-मिगिंग खंड पर दो पैकेज, खरसांग-मायो-गांधीग्राम-विजय नगर खंड का प्रबंधन करने वाले पैकेज 2 और 4 और बॉमडिला-नाफ्रा-लादा खंड पर ध्यान केंद्रित करने वाला पैकेज 1 शामिल हैं ।

मंत्री ने कहा कि इन हाईवे खंडों के विकास से सीमावर्ती क्षेत्रों की संपर्क क्षमता बढ़ाने और क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है ।

उन्होंने कहा कि फ्रंटियर हाइवे के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर पलायन कम होने और वापसी पलायन की सुविधा मिलने की संभावना है ।

X पर एक अलग पोस्ट में गडकरी ने कहा कि MoRTH ने नेशनल हाईवे-716 पर तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा से पुत्तूर (20.03 किमी) तक मौजूदा दो-लेन वाले पक्के कंधे के विस्तार के लिए 1,346.81 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है ।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना में इसे चार-लेन कंफीग्यूरेशन में पक्के कंधे के साथ एडवांस करना शामिल है ।

दिल्ली कैंट-अजमेर वंदे भारत को चंडीगढ़ तक मिला विस्तार

प्रधानमंत्री ने उत्तर रेलवे की चार समेत दस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई

परिवहन विशेष न्यूज

- निजामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत की नियमित सेवा 15 से शुरू होगी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रेलवे की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया । उन्होंने विभिन्न दिशाओं में चलने वाली 10 नई वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी भी दिखाई । इनमें से चार बंदे भारत का संचालन उत्तर रेलवे करेगा । इनमें निजामुद्दी-खजुराहो, पटना-लखनऊ, लखपनऊ-देहरादून और वाराणसी-रांची वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं । इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी-पटना, पुरी-विशाखापत्तनम, कलबुर्गी-सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, अहमदाबाद-मुंबई मध्य, सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम,

मैसूरु- डॉ. एमजीआर मध्य (चेन्नई) के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी । इसके साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी । चार वंदे भारत ट्रेनों को विस्तार भी दिया गया है । दिल्ली सराय रोहिल्ला-अजमेर वंदे भारत अब चंडीगढ़ तक चलेगी । इसके अलावा गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज तक और तिरुवनंतपुरम-कासरगोड वंदे भारत को मंगलुरु तक विस्तार दे दिया गया है ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में 2 माल गोदाम, जन औषधि केंद्र, एक कोच रेस्तरां, आनंद विहार-तिलक ब्रिज तीसरी और चौथी रेल लाइन, 48 एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट, 17 डीएफसी (कार्गो हैंडलिंग पॉइंट) का लोकार्पण इस मौके पर किया । आनंद विहार में वॉशिंग कम पिट-लाइनों पर कवर शेड की आधारशिला रखी गई । इसके अलावा बिजवासन में प्रशिक्षण सुविधा और आनंद विहार में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव के लिए एक ट्रेन सेट डिपो का निर्माण किया जाएगा ।

ट्रेन संख्या 22470/22469 हजरत निजामुद्दीन-खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में छह दिन, सोमवार को छोड़कर दोनों तरफ से चलेगी । इस ट्रेन की नियमित सेवा 15 मार्च से शुरू होगी । ट्रेन संख्या 20887/20888 रांची-वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस बृहस्पतिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन दोनों दिशाओं से चलेगी । इस ट्रेन की नियमित सेवा 18 मार्च से शुरू होगी । ट्रेन संख्या 22345/22346 पटना—गोमतीनगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी । इस ट्रेन की नियमित सेवा दोनों तरफ से 18 मार्च से शुरू होगी । इसके अलावा बृहस्पतिवार से ट्रेन संख्या 20977/20978 अजमेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस चंडीगढ़ तक चलेगी । वापसी दिशा में भी चंडीगढ़ से ही दिल्ली कैंट आएगी । इसके अलावा ट्रेन संख्या 22549/22550 गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रयागराज तक विस्तार दे दिया गया है ।

हरदिन करीब 500 टन ठोस कचरे का निपटान होगा, लेकिन कूड़े की दुर्गंध लोगों को परेशान नहीं करेगी।

देश की पहली इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट खुली, 15 एकड़ क्षेत्रफल में है फैला; क्षमता 9.65 लाख मीट्रिक टन

परिवहन विशेष न्यूज

इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट चालू होने के बाद अब ओखला लैंडफिल साइट के कूड़े से निकलने वाली दुर्गंध से निजात मिलेगी । ओखला लैंडफिल साइट के बगल तेहखंड में 15 .47 एकड़ क्षेत्रफल में इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट को बनाया गया है ।

नई दिल्ली । दक्षिण पूर्व दिल्ली में मंगलवार को खोली गई इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट से न ही मिट्टी दूषित होगी और भूजल व हवा मैली नहीं होगी । हरदिन करीब 500 टन ठोस कचरे का निपटान होगा, लेकिन कूड़े की दुर्गंध लोगों को परेशान नहीं करेगी । ओखला के तेहखंड में करीब दो साल में बनकर तैयार देश की पहली इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट का एलजी वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक साथ मिलकर उद्घाटन किया ।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस आधुनिक प्लांट में कूड़े के निस्तारण के बाद निकली राख को प्रोसेस करने की व्यवस्था होगी । दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए इनकी सरकार लगातार काम कर रही है और इसमें सफलता मिल रही है । एलजी और सीएम ने इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट पर नामपट्टिका का अनावरण किया और नारियल फोड़कर परियोजना की शुरुआत की गई । इसके बाद दोनों ने प्लांट का फाइनल मॉडल देखा और इंजीनियर्स से प्रोजेक्ट की जानकारी ली । नगर निगम की कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया । इधर एलजी ने कहा, इस अत्याधुनिक संयंत्र के चालू हो जाने से कूड़े के वैज्ञानिक निपटान में काफी सहायता मिलेगी । इस दौरान मेयर डॉ शैली ओबरॉय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल समेत एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे ।

नहीं दिखेगी कूड़ा, दुर्गंध से मिलेगी निजात

इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट चालू होने के बाद अब ओखला लैंडफिल साइट के कूड़े से निकलने वाली दुर्गंध से निजात मिलेगी । ओखला लैंडफिल साइट के बगल तेहखंड में 15.47 एकड़ क्षेत्रफल में इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट को बनाया गया है । इसकी क्षमता 9.65 लाख मीट्रिक टन है । वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से निकली हुई राख को इसमें निस्तारित किया जाएगा । इस राख को डालने के लिए एमसीडी को 300 रुपये प्रति टन के हिसाब से राशि मिलेगी । यहां रोजाना करीब 500 टन राख डाली जाएगी । इसके अलावा 100 किलो लीटर हरदिन छमता का लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है । करीब आधे एकड़ में लीचेट प्लांट को बनाया गया है । लैंडफिल साइट के आस पास ग्रीन एरिया बनाने के लिए इसके 7.42 एकड़ क्षेत्र को रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के रूप में रखा गया है । इसके निर्माण में 42.31 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ।

वैज्ञानिक तकनीक से बनी है लैंडफिल साइट

इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट वैज्ञानिक तरीके से बनी है । इसमें पहले सात मीटर गड्ढा खोदकर मिट्टी की दो परत डाली गई है । उसके बाद तीन परत लाइनर की डाली गई है । फिर पाइपलाइन डालकर फिर से एक परत लाइनर और एक परत मिट्टी डालकर तैयार किया है ।

अन्य साइटों से बिल्कुल अलग

देश की ये पहली इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट अन्य लैंडफिल साइट से बिल्कुल अलग है । दिल्ली में मौजूदा समय हरदिन करीब 12000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है । ठोस या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जले कचरे की राख के रूप में ये कूड़ा दिल्ली की तीन लैंडफिल साइटों पर ही जाता है । बारिश के दिनों में लैंडफिल साइटों पर जमा लिचेट जमीन में चला जाता है । इसकी वजह से भूजल प्रदूषित होता है ।

पार्टनर के साथ ये 4 चीजें करना, धीरे-धीरे घोंट सकती है रिश्ते का गला; आप तो नहीं कर रहे ऐसी गलती

गौरव खरे

कपल्स को अपने रिश्ते को लंबा चलाने के लिए छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जरा सी भी गलती रिश्तों की सूरत बदल देती है। ऐसे में यदि आप अपने खूबसूरत रिश्ते को बदरंग होता नहीं देखना चाहते हैं तो इन बातों पर गौर कर लें।

कई बार जाने-अनजाने हम अपने पार्टनर और रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पाते और कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो साइलंट किलर की तरह आपके रिश्ते को बर्बाद करने लगता है। ऐसे में कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, ताकि आपका लॉन्ग टर्म का रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहे।

दबी हुई कड़वाहट का बाहर आना

अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आता है, तो उसी वक्त उसे पार्टनर के सामने एक्सप्रेस कर दें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप उस वक्त अपने गुस्से, निराशा और कुंठा को दबा लेते हैं, तो यह दबी हुई कड़वाहट भविष्य में जब बाहर निकलती है, तब रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कई सालों की शादी में ज्यादा होता है।

एक-दूसरे के बारे में पूर्वधारणाएं रखना

अगर कोई कपल इस बात को लेकर खुशी महसूस करता है कि वह दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो यह अच्छा संकेत भी हो सकता है और बुरा भी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो लोग क्या इतने करीब हो सकते हैं कि वे एक-दूसरे का दिमाग पढ़ने लगें या फिर ये सिर्फ पूर्व धारणाएं हैं? ऐसे में सिर्फ यह मान लेना कि आप पार्टनर की पसंद-नापसंद को अच्छी तरह से जानते हैं और उसके हिसाब से काम करना भी रिश्ते के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। इसलिए पहले से चीजें मान लेने की बजाए पार्टनर को खुद अपनी भावनाएं जाहिर करने दें।

सरप्राइज न हो तो बोरिंग जिंदगी

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्ते का शुरुआती दौर इतना रोमांटिक और एक्साइटिंग क्यों होता है? यह वो समय होता है, जब दोनों पार्टनर एक-दूसरे के बारे में नई-नई चीजें जान रहे होते हैं। सरप्राइज किसी भी रिश्ते को एक्साइटिंग बना देता है।
लेकिन अगर समय के साथ रिश्ते में सरप्राइज कम होने लगे तो रिश्ता बोरिंग हो सकता है। लिहाजा कभी-कभार अचानक ही प्यार भरी बातें, डिनर डेट जैसी चीजें करते रहना चाहिए।

पार्टनर या रिश्ते को हल्के में लेना

कई बार मजबूत और स्थिर रिश्ते में भी दरार सिर्फ इस एक वजह से आ जाती है, क्योंकि एक पार्टनर, दूसरे पार्टनर को या फिर अपने रिश्ते को हल्के में लेने लगता है।
यह इंसान की फितरत होती है कि जब इंसान किसी के साथ लंबे वक्त तक रहता है, तो उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। ऐसे में इस गलत आदत को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी रूटीन को बदलें।

बस 6 स्टेप्स में घर के गार्डन में उगाएं ब्रोकली, बाजार में नहीं करना पड़ेगा मोल भाव

यदि आपको ब्रोकली खाना पसंद है तो आप इसे बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में उगाकर खा सकते हैं। यहां हम आपको घर में ब्रोकली उगाने का स्टेप टू स्टेप तरीका बता रहे हैं।

गोभी की तरह दिखने वाला ब्रोकली सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें बहुत ही ताकतवर पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बाउल मूवमेंट को स्वस्थ रखने के साथ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा वेट लॉस में भी इसे कारगर बताया गया है।

वैसे तो आप इसे बाजार में बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपको मोल भाव से बचना है तो इसे अपने गार्डन में उगाना एक जबरदस्त आइडिया है। ऐसा करके आप बहुत ही सस्ते में ऑर्गेनिक ब्रोकली का लाभ उठा सकते हैं।

स्टेप 1

ब्रोकली उगाने के लिए चूने के साथ मिट्टी मिलाएं और इसे एक सप्ताह तक सुखाएं। प्रत्येक ग्रो बैग के लिए, 5 ग्राम चुना डालें। एक सप्ताह तक सीधी धूप में सुखाने के बाद, गोबर पाउडर या खाद जैसी जैविक खाद डालें।

आप इसमें कोको पीट भी मिला सकते हैं। सुनिश्चित करें कि गमले की मिट्टी ना तो ज्यादा सूखी हो ना ही ज्यादा गीली हो। क्योंकि इससे बीज खराब हो जाते हैं।

स्टेप 2

आप ब्रोकली के बीज या कटिंग दोनों की मदद से उगा सकते हैं। इसका बीज आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। इससे ब्रोकली को उगाने के लिए इसे ट्रे या गमले में बोएं और अंकुरित होने के लिए छोड़ दें।

स्टेप 3

ब्रोकली के कटिंग या अंकुरण को मिट्टी के मिश्रण के साथ ग्रो बैग के 1/4 हिस्से में लगाएं। जैसे-जैसे पौधा बढ़े, ग्रो बैग में मिट्टी डालते जाएं ताकि इसे तेजी से बढ़ने और बड़ी ब्रोकली के सिर बनाने में मदद मिल सके।

स्टेप 4

गमले की मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए यदि जरूरत पड़े तो इसमें समय-समय पर पानी भी डालते रहें। ध्यान रखें आपको मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं डालना है। सिर्फ नमी को बरकरार रखने के लिए पानी का छिड़काव करना है।

स्टेप 5

जब ब्रोकली के बीज अंकुरित हो जाए तब इसे आप चाहे तो ट्रे या पॉट से निकालकर सीधे जमीन में भी लगा सकते हैं।

स्टेप 6

अंकुरित बीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर लगाने से पहले इसे 30 मिनट के लिए स्यूडोमोनास तरल में पौधों की जड़ों को डुबोएं। ऐसा करने से इसकी जड़ें मजबूत होती है।

वक्त पर पकड़ना है काला मोतिया तो एक बार करें ये काम, पॉल्यूशन का जंजाल होगा खत्म

पॉल्यूशन के कारण लोगों को आंखों में जलन, एलर्जी और गले में खराश जैसी परेशानियां हो रही हैं। इससे बचने के लिए विशेष टिप्स दिए गए हैं। आंखों की जांच और डाइलेट करने से आंखों की परेशानियों को समझना आसान होता है। मोबाइल का अधिक इस्तेमाल मायोपिया को बढ़ावा देता है।

पॉल्यूशन ने अपना जोर लगाया हुआ है। लोगों को इस वजह से आंखों में जलन, सांसों की परेशानी, एलर्जी की शिकायत, गले में खराश समेत तमाम तरह की परेशानियों ने घेर रखा है। साथ ही मौसम बदल रहा है और त्योहारों का सीजन भी चल रहा है।

ऐसे में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सेहतमंद बने रहने के लिए बेस्ट टिप्स। इन्हें अपनाकर आप खुद को अच्छी सेहत का तोहफा दे सकते हैं।

1. साल में एक बार आई चेकअप

साल में एक बार आंखों की जांच होनी चाहिए, वह भी आंखों को डाइलेट करके। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से टेस्टिंग होती है। लेकिन आंखों की अंदरूनी परेशानी का पता लगाने के लिए डाइलेट करने के खास लिक्विड (Tropicamide, Phenylephrine Hydrochloride) की चंद बूंदें आंखों में डाली जाती हैं।

इससे डॉक्टर को आंखों के भीतरी हिस्से, नसें आदि अच्छी तरह दिख जाती हैं। इससे आंखों की परेशानियों को समझना आसान हो जाता है। इस जांच का चलन ज्यादातर शुगर पेशेंट्स और उम्र से जुड़ी परेशानियों में होता है।

फिर भी इस तरह की जांच सभी के लिए होनी चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हर साल आंखों का प्रेशर जरूर चेक कराएं। इससे काला मोतिया वक्त पर पकड़ में आ जाता है।

2. मोबाइल से दूरी

मोबाइल की जरूरत सभी को है। काफी संख्या में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनकी यह जरूरत लत बन गई है। लेकिन 6 से 13 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। इससे मायोपिया हो रहा है।

इसमें दूर की निगाह कमजोर हो जाती है। किसी शख्स को 6 फुट की दूरी पर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट साफ दिखाई न दे तो इसका मतलब है कि वह मायोपिया का शिकार हो सकता है।

ज्यादातर बच्चे मायोपिया वाले ही होते हैं। आम रुटीन में हम एक मिनट में 20 से 25 बार पलकों को झपकाते हैं, लेकिन स्क्रीन देखते समय यह महज 5 से 7 बार रह जाती है।

3. 20:20:20 फॉर्मूला

अगर कोई शख्स किसी से बात कर रहा हो, कहीं जा रहा हो तो वह स्वाभाविक तौर पर कभी नजदीक तो कभी दूर देखता रहता है। लगातार नजदीक देखने का मसला नहीं बनता। लेकिन जब कोई शख्स लगातार मोबाइल या लैपटॉप आदि की स्क्रीन को देखता रहता है तो 'दूरदर्शन' की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे शख्स को 20:20:20 फॉर्मूले पर अमल करना जरूरी है यानी हर 20 मिनट बाद 20 बार पलकें झपकना, फिर लगातार 20 सेकंड तक 20 फुट या इससे दूर देखना चाहिए।

इससे आंखों को आराम मिलता है। साथ ही ड्राई आंखों की परेशानी भी कम होती है। इसके अलावा स्क्रीन पर काम करते हुए बार-बार पलकें झपकाएं। याद रखें, हर 5 सेकंड में एक बार पलकें झपकनी चाहिए।

उबला अंडा या ऑमलेट, कौन देता है सबसे ज्यादा ताकत?

अंडे के अपने हेल्थ बेनिफिट्स है। अंडा को प्रोटीन का रिच सोर्स माना जाता है। लोग इसे अलग-अलग तरीके से खाते हैं। कोई उबालकर खाना पसंद करता है तो कोई ऑमलेट बनाकर, लेकिन किस तरह से खाने से सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं।

संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे...ये कहावत आपके कई बार सुनी और सुनाई होगी। अंडा खाना हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसे प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स माना जाता है। जिम में पसीना बहाने वाले लोग अपनी डाइट में अंडे को जरूर शामिल करते हैं। दुनियाभर में लोग अंडे को अलग-अलग तरीके से खाना पसंद करते हैं। अगर यूं कहे कि अंडा सबसे पॉपुलर ब्रेकफास्ट ऑप्शन है तो गलत नहीं होगा।

कई पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह से अंडे का ऑमलेट और ब्रेड भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला ब्रेकफास्ट है। लोग उबले हुए अंडे को खाना भी उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे को उबालकर खाना ज्यादा अच्छा है या फिर ऑमलेट बनाकर? किस तरह से खाने में ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं? उबला अंडा या फिर ऑमलेट में अंडे के ज्यादा पोषक तत्व मौजूद रहते हैं?

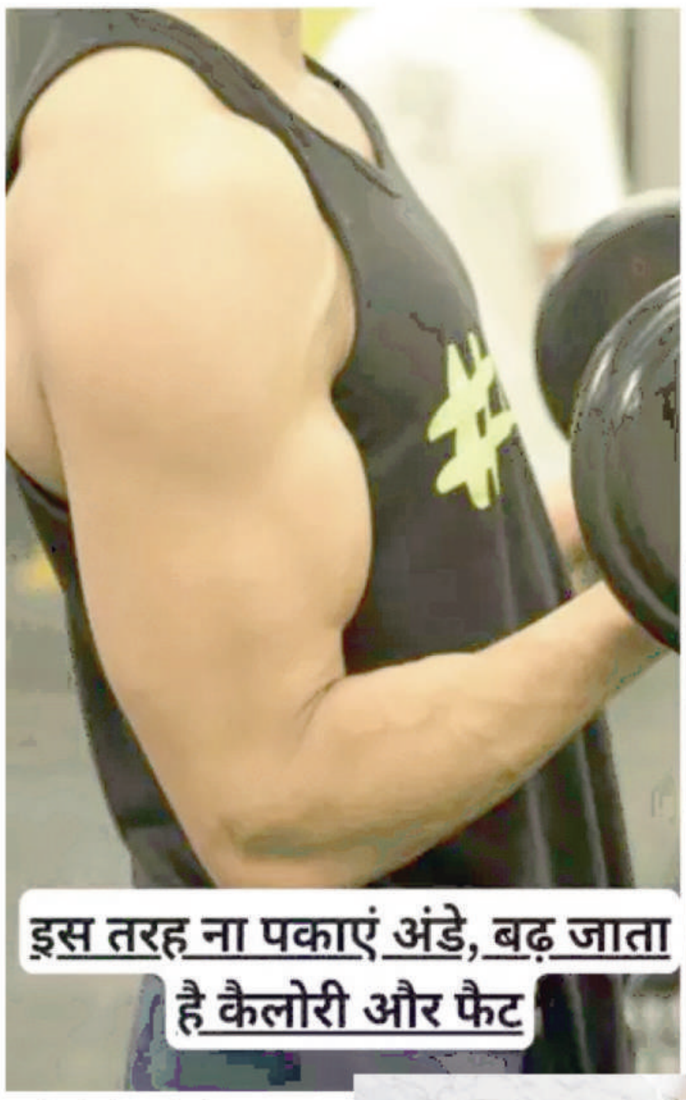

अंडे का फंडा

अंडे में मौजूद पोषक गुणों के कारण लोग इसे खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग उबला अंडा पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ इसका ऑमलेट बनाकर खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों तरीकों में से कौन-सा तरीका आपके लिए ज्यादा सेहतमंद है। आज हम इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। अंडे में मौजूद प्रोटीन आपकी मसल्स को रिपेयर करने और उनके ग्रोथ में मदद करता है।

अंडे में मौजूद विटामिन डी, बी12 और राइबोफ्लेविन शरीर को क्विक एनर्जी पहुंचाते हैं। अंडे में प्रचुर मात्रा में कोलीन होता है, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य और उसके विकास में मदद करते हैं। अंडे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। वहीं अंडे में मौजूद अनसैचुरेटेड फैट शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करता है।

उबला अंडा या फिर ऑमलेट

अंडे को उबालकर खाना काफी पुराना और अच्छा तरीका है। उबले अंडे में पोषण तत्व भरपूर होते है। एक उबले अंडे में करीब 78 कैलोरी होती है। प्रोटीन के अलावा फैट, विटामिन-मिनरल्स होता है। उबले अंडे विटामिन बी12, डी और राइबोफ्लेविन भरपूर होता है। ये मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। उबले अंडे में बाहर से कुछ भी मिलावट नहीं होती। अलग से कोई तेल या मसाला नहीं होता। इसलिए उबले अंडे में पोषक तत्व भरपूर होते हैं।

ऑमलेट

ऑमलेट खाना बहुत लोगों को पंसद है। ब्रेड-ऑमलेट लोगों को फेवरेट ब्रेकफास्ट है। आमतौर पर लोग ऑमलेट में प्याज, मिर्च, नमक, मसाले मिलाकर बनाते है। इसे बनाने में तेल या रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी वजह से इसमें कैलोरी और अनहेल्दी फैट ज्यादा हो जाता है। तेल या बटर के साथ पकाने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा फैट एड हो जाता है।

तो फिर कौन सा ज्यादा सेहतमंद

दोनों के बारे में जानकर आप समझ गए होंगे कि अंडे का कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। चूंकि ऑमलेट बनाने के दौरान उसमें एक्स्ट्रा फैट, मसाले एड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। वहीं अंडे को उबालने की प्रक्रिया में उसके सभी पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इसलिए अगर आपको अंडे का मैक्सिमम पोषक तत्व चाहिए तो बेहतर हैं कि उसे ऑमलेट के बजाए उबालकर खाएं।

लोस चुनाव : लोगों की चाहत- विकसित देशों की राह पकड़े एनसीआर, लेकिन शहरो में नहीं होता कूड़े का निपटान

एनसीआर के शहरों की आकांक्षा विकसित देशों से कदम ताल करने की है। लोग चाहते हैं कि आने वाले पांच साल में उनके शहर की गिनती दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में हो। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल स्वच्छता के मुद्दे को न सिर्फ अपने एजेंडे में शामिल करें बल्कि उसके लिए पांच वर्ष तक गंभीरता से काम करें।

स्वच्छ रैंकिग में दिल्ली एनसीआर के जिले

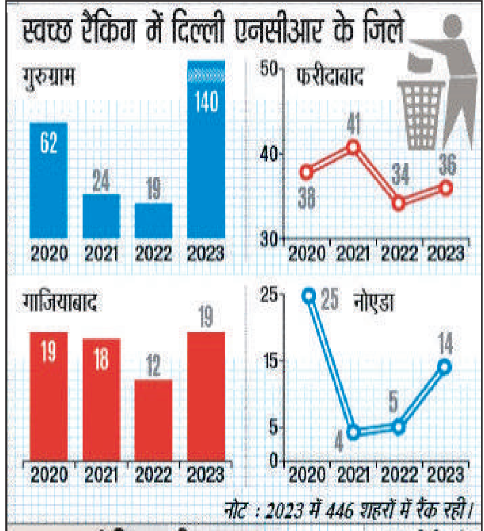

नोट : 2023 में 446 शहरों में रैंक रही।

स्वच्छता रैकिंग परिणाम 2023

90 एमसीडी | 7 एनडीएमसी | 7 दिल्ली कैंट (61 में से)

(एमसीडी और एनडीएमसी की रैंकिग 446 में से है)

कूड़ा निकलने व उसके निस्तारण की स्थिति

निकाय	निकल रहा	निस्तारण	लैंडफिल पर जा रहा
दिल्ली	11300	7279	4021
गाजियाबाद	1500	200	1300
फरीदाबाद	850	15	835
गुरुग्राम	1200	250	950
सोनीपत	200	200	0
नोएडा	1100	400	700
कुल	16150	8344	7806

12.5 प्रतिशत वार्डों में ही लोग साफ-सफाई को गंभीरता से ले रहे हैं

88 प्रतिशत वार्ड निवासी सब्जी के छिलके, प्लास्टिक, पालीथिन सब एक ही कूड़ेदान में डाल रहे हैं

कितने वार्ड हैं और कितने में 100 प्रतिशत गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग होता है

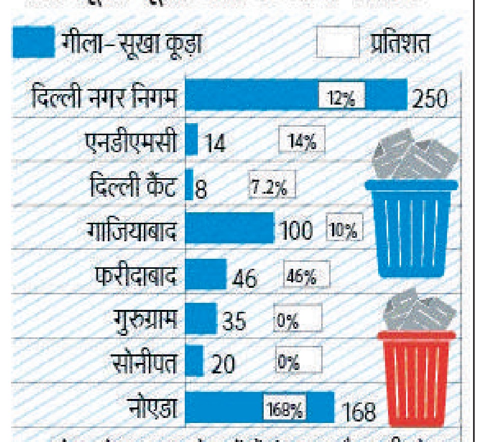

नोट : नोएडा 168 सेक्टरों में बंटा हुआ है। सभी सेक्टर में गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग हो रहा है लेकिन इन सेक्टरों में बसे 81 गांव में प्राधिकरण को गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग कराने में सफलता नहीं मिली है।

नई दिल्ली। एनसीआर के शहरों की आकांक्षा विकसित देशों से कदम ताल करने की है। लोग चाहते हैं कि आने वाले पांच साल में उनके शहर की गिनती दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में हो।

इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल स्वच्छता के मुद्दे को न सिर्फ अपने एजेंडे में शामिल करें, बल्कि उसके लिए पांच वर्ष तक गंभीरता से काम करें।

एनसीआर को साफ-सुथरा करने में क्या बाधा है और इसका निस्तारण कैसे हो सकता है। इसे लेकर पेश है निहाल सिंह की रिपोर्ट-

आरडब्ल्यूए एक्ट में बदलाव की जरूरत

जिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की कालोनी या फिर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका होती है। दिल्ली नगर निगम की ब्रांड एबेंसडर स्वच्छता डा. रूबी मखीजा ने बताया कि कई कालोनियों में आरडब्ल्यूए अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन एक-एक कालोनी में तीन से चार आरडब्ल्यूए हैं।

अब आरडब्ल्यूए एक्ट के तहत यह बाध्यता नहीं है कि एक ही आरडब्ल्यूए कालोनी में काम करेगी। किसी कालोनी के सात लोग मिलकर आरडब्ल्यूए बना सकते हैं। ऐसे में, एक आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। इसलिए इसके लिए एक्ट में ही बदलाव करने की जरूरत है।

सांसद जो चुनकर आए वह आरडब्ल्यूए एक्ट को नए सिरे से बनाने की आवाज उठा सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि 1860 के बने आरडब्ल्यूए एक्ट में बदलाव करें और यह सुनिश्चित करें कि आरडब्ल्यूए की जिम्मेदीर भी सुनिश्चित हो।

क्या होता है गीला कूड़ा

अंडे के छिलके, चिकन की हड्डियां, सड़े फल सब्जियां, गंदा टिशू पेपर, चाय-काफी के बैग, पत्ते की प्लेट, पूजा सामग्री फूल राख आदि।

क्या होता है सूखा कूड़ा

कागज, कांच, प्लास्टिक, रबर, कार्डबोर्ड, स्टायरोफोम, धातु, खाद्य पैकेजिंग सामग्री आदि

सांसदों से लोगों की आकांक्षाएं

सांसद निधि का उपयोग स्वच्छता के कार्यों में लगे, जिससे मदद मिले

आरडब्ल्यूए एक्ट में सुधार की जरूरत, 1860 के एक्ट को बदलने की मांग

एनसीआर में पूरी तरह गीला-सूखा कूड़ा अलग करने का लक्ष्य पूरा हो

सांसद निधि से शौचालयों से लेकर गीले कूड़े के निस्तारण के प्लांट बनवाएं

निगमों के पास जो संसाधन नहीं है, उसके लिए केंद्र से अतिरिक्त फंड दिलवाएं

लोगों को जागरूक करें और कोई कालोनी में जाएं तो उसके लिए स्वच्छता को देखकर अधिकारियों से सुनिश्चित कराएं कि कालोनी में स्वच्छता रहे

सांसद बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मिलकर सीएसआर के तहत निगमों को फंड दिलवा सकते हैं

गैस व खाद बनाने के लगाने होंगे प्लांट

एनसीआर के सभी शहरों में कूड़े के पहाड़ बड़ी समस्या हैं। इसकी बड़ी वजह कूड़े से गैस व खाद बनाने वाले पर्याप्त प्लांट नहीं होना है। प्लांटों को प्राथमिकता के साथ लगवाने के साथ ही शहर का सौ प्रतिशत गीला और सूखा कूड़ा यहां पहुंचाया जाए, तो स्वच्छता के नए मापदंड तय किए जा सकते हैं। सांसद भी गीले कूड़े से खाद बनाने के लिए अपनी निधि का वर्षानुसार खर्च कर अपने क्षेत्र की 10 कालोनियों और गांव में व्यवस्था कर सकते हैं।

एनसीआर में सिर्फ 50 प्रतिशत ही आधुनिक तरीके से कूड़े का निपटान

एनसीआर में सिर्फ 50 प्रतिशत ही आधुनिक तरीके से कूड़े का निपटान एनसीआर में आधुनिक तरीके से कूड़े के निस्तारण 50 प्रतिशत ही हो पा रहा है। शेष कूड़ा लैंडफिल पर जा रहा है। इससे पर्यावरण तो दूषित हो रहा है, जबकि एनसीआर का स्वच्छता की आंकक्षा पूरी होने में बाधा बन रहा है। इसके जरुरी है कि सौ प्रतिशत गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग किया जाए और जो कूड़ा बच रहा है उसे लैंडफिल पर डालने की बजाय आधुनिक तरीके से निष्पादित किया जाए।

स्वच्छता की राह में ये भी बड़ी बाधा

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली कैंट और एनडीएमसी में कुल वार्ड या सर्किल की संख्या 272 हैं। इसमें से मात्र 34 वार्ड शत प्रतिशत गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग कर रहे हैं। फरीदाबाद के 46 में से एक भी वार्ड लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। सोनीपत और गुरुग्राम की भी यही स्थिति हैं। इसी प्रकार गाजियाबाद 10 वार्ड ही लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं।

*कूड़े को सिर्फ लोग गंदगी तक सीमित रखते हैं, लेकिन यह एक काला सोना है, जिसे खाद बनाकर कई कंपनियां आनलाइन बेच रही हैं, जबकि यह खाद घर पर ही बना सकते हैं। फिर क्यों हम कूड़ा फेंक रहे हैं, अगर हर घर से गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग होने लगे और गीले कूड़े की खाद बनने लगे तो कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जा सकता है। सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 में प्रविधान है कि प्रत्येक घरों से कुछ राशि कूड़ा निस्तारण के लिए वसूली जाए। जब राशि वसूली जाएगी तो लोग संभवत: कूड़ा देना बंद करेंगे या कम करेंगे। इससे स्वच्छता का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। **-जगदीश ममगांई, पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम की निर्माण समिति***

मुस्लिम संगठनों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के अधिसूचना की निंदा की

शम्स आगाज़ जामेई

नई दिल्ली। हम, अधोहस्ताक्षरी संगठन समानता और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करने वाले भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ अपना एकीकृत रुख व्यक्त करने के लिए यह संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी करते हैं। हम आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 को लागू करने की कड़ी निंदा करते हैं।यह अधिनियम ऐसे प्रावधानों का परिचय देता है जो भारतीय संविधान में निहित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांतों का प्रतीक है और धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच अनुचित भेदभाव को रोकता है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2 में खंड (बी) का सम्मिलन कि 'अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्ति, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया' उल्लेख करके पक्षपातपूर्ण व्यवहार स्थापित करता है। जबकि इस अधिनियम में धर्म के आधार पर मुसलमानों को शामिल करने से बचा गया है, इसने नागरिकों के बीच समान अधिकारों के सिद्धांत को गंभीर झटका दिया है; इस प्रकार कानून के तहत समान व्यवहार के सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है। यह भेदभावपूर्ण कानून देश के सामाजिक ताने-बाने को खतरे में डालता है, जिससे समावेशिता और विविधता के मूलभूत सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं।

भारतीय संसद द्वारा नागरिक संशोधन विधेयक की मंजूरी उपरांत देश भर के मुसलमानों और समाज के अन्य वर्गों ने, जिन्होंने भारत के संविधान की रक्षा के लिए तत्काल जिम्मेदारी महसूस की विरोध प्रदर्शन किया। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए चुना गया समय भी प्रश्न खड़ा करता है और संकीर्ण सोच वाले राजनीतिक हितों के लिए समाज में धार्मिक विभाजन पैदा करने के स्पष्ट राजनीतिक मकसद को दर्शाता है।हमारा मानना है कि नागरिकता धर्म, जाति या पंथ के भेदभाव बिना समानता के सिद्धांतों के आधार पर दी जानी चाहिए। अधिनियम के प्रावधान सीधे तौर पर इन सिद्धांतों का खंडन करते हैं और हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरे में डालते हैं।

हम सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को निरस्त करने और भारतीय संविधान में निहित समावेशिता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह करते हैं।

हस्ताक्षरित:

मौलाना महमूद असद मदनी: अध्यक्ष, जमीयत उलेमा-ए-हिंद

सैयद सदातुल्लाह हुसैनी: अमीर, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

मौलाना असगर इमाम मेहदी सलफी: अमीर, जमीयत अहले हदीस हिंद

मौलाना फैसल वली रहमानी: अमीर, इमारत ए शरिया

मौलाना अनीसुर रहमान कासमी: उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल

मौलाना यासीन उस्मानी बदायूँनी: उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल

मलिक मोतसिम खान: उपाध्यक्ष जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

मोहम्मद सलीम इंजीनियर: उपाध्यक्ष जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

मौलाना हकीमुद्दीन कासमी: महासचिव जमीअतुल उलेमा हिंद

डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास

मौलाना नियाज फारूकी

शेख मुजतबा फारूक

डॉ. जफरुल-इस्लाम खान, पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग

दिल्ली कमेटी के चहेते निशान सिंह मान का अभिमान तोड़ कर हरदीप सिंह ने जीत दर्ज की

उदय विहार की संगत द्वारा गुरुद्वारा चुनाव में अकाली दल पर लगाई गई मोहर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली, बीते दिनों उदय विहार की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को संगत ने सेवा सौंपी। इस चुनाव में संगत द्वारा दिल्ली गुरूद्वारा कमेटी के सदस्य अनूप सिंह घुम्मण के करीबी हरदीप सिंह को सेवा सैंपी गयी। दूसरी ओर निशन सिंह मान के गुट को करारी हार का सामना करना पड़ा।

अनूप सिंह घुम्मण ने कहा कि निशान सिंह मान व दिल्ली गुरूद्वारा कमेटी ने सभी प्रकार के पैंतरे अपनाते हुए जीतने का प्रयास किया। लेकिन संगत ने इन्हें बुरी तरह हराते हुए अकाली दल को सेवा का मौका दिया।

इस जीत के साथ दिल्ली के पंथक क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल व व परमजीत सिंह सरना का गौरव बढ़ा है।

इस जीत के लिए सरदार सरना ने अनूप सिंह घूम्मण सदस्य दिल्ली कमेटी व अध्यक्ष चुने गए हरदीप सिंह सहित उनकी समूची टीम को बधाई दी। इस मौके पर हरदीप सिंह के साथ कंवलजीत सिंह नीटू वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुखजीत सिंह पप्पू सचिव, स. जसविंदर सिंह बिल्ला को कोषाध्यक्ष चुना गया।

इस दौरान अन्य लोगों के अलावा बलविंदर शर्मा ने भी नवनिर्वाचित कमेटी को बधाई दी।

मोदी के रहते 7वें सीएम बने टार्गेट, गंवाई कुर्सी

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। हरियाणा में तेजी से घटे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोदी के पीएम कार्यकाल में सीएम पद की कुर्सी गंवाने वाले अब 7वें शख्स में शुमार हो गए हैं।

बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड, त्रिपुरा, से लेकर महाराष्ट्र तक में खेला हो चुका है। अब हरियाणा भी लिस्ट में शामिल हो गया है।

उत्तराखंड में त्रिवेन्द्र सिंहरावत, 18 ,मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बने थे।लेकिन कार्यकाल पूरा करने स पहले ही बीजेपी हाईकमान ने सत्ता बदल दी। त्रिवेन्द्र सिंह रावत को 10 मार्च, 2021 को 3 साल 357 दिन बाद इस्तीफा देना पडा। इनकी जगह तीरथ सिंह रावत को सत्ता सौंप दी। तीर्थ सिंह रावत भी कुल 116 दिन ही कुर्सी पकड पाए।

इसके बाद 2014 में मोदी पीएम की गद्दीनशीन होने के बाद आनंदी बेन पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पटेल को सिर्फ 2 साल 77 दिनों के कार्यकाल के बाद इस्तीफा देना पडा। फिलहाल वे सक्रिय राजनीति से दूर उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। इसी क्रम में गुजरात में विजय रूपाणी के सीएम रहते ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता था।लेकिन वह भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्हें हटाकर बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। वहीं कर्नाटक में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत हांसिल करने के बाद बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया।लेकिन 3 ही दिन में उन्हें पद छोडना पडा। तब कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1 साल 61 दिन बाद फिर से येदियुरप्पा कर्नाटक की 15 वीं विधानसभा में सीएम बन गए। इस बार भी वह कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और बीजेपी ने उन्हें हटाकर बसवाराज बॉम्बई को सीएम बना दिया। अब आते है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014 में जीत के बाद बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार बनी और सीएम देवेन्द्र फडण्वीस बने थे।2019 के नवंबर में शिवसेना ने चुनाव पूर्ण गठबंधन खत्सम कर दिया जिसके बाद अजित पवार के समर्थन से उन्होंने आनन-फानन में सीएम पद की शपथ ली।हालांकि 5 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद उदव ठाकरे सीएम बने, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद वह भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।

मनोहर लाल का जाना एक साल पहले ही हो गया था तय, पूर्व सीएम ने खुद बताई विदाई की वजह

परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा में सरकार का मुखिया बदलने का निर्णय दिल्ली में भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में हो गया था। चंडीगढ़ में नया नेता चुने जाने के लिए हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में स्वयं मनोहर लाल ने इसकी जानकारी दी। बिप्लब कुमार देब के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ नए नेता के चुनाव के लिए पहुंचे हुए थे।

नई दिल्ली। हरियाणा में सरकार का मुखिया बदलने का निर्णय दिल्ली में भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में हो गया था। चंडीगढ़ में नया नेता चुने जाने के लिए हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में स्वयं मनोहर लाल ने इसकी जानकारी दी।

इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ नए नेता के चुनाव के लिए पहुंचे हुए थे। बैठक शुरू होते ही राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि बैठक की कार्यवाही के बारे में मनोहर लाल बताएंगे।

नए चेहरों की जरूरत

इसके बाद मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी का विचार है कि संगठन और सरकार में नए चेहरे काम करें। इसलिए मैंने एक साल पहले ही पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया था कि मैंने प्रदेश में आठ साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए सेवा दी है, अब किसी अन्य नेता को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। पार्टी में व्यवस्था है कि नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। पुराने अलग भूमिका निभाते हैं।

राज्य में नेतृत्व के परिवर्तन के लिए हुआ मंथन

मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी में उनके इस आग्रह पर गहन मंथन हुआ, इसमें समय लगा और अब संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। पार्टी ने निर्णय लिया है कि कुरुक्षेत्र से सांसद और प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे नायब सैनी को भाजपा विधायक दल का नया नेता बनाया जाए।

विधायकों ने सर्वसम्मति से किया पारित

इसके बाद मनोहर लाल ने नायब सैनी का नाम विधायक दल के नए नेता के रूप में प्रस्ताव विधायकों के समक्ष रखा। इसका अनुमोदन सबसे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर फिर पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल और पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया। इसके बाद नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

हरियाणा में नयाब सैनी सरकार, मनोहर खट्टर बाहर अब एमपी का लडेगें चुनाव, या होंगे नड्डा पर सवार

परिवहन विशेष। लोकसभा चुनाव से पहले अद्भुत तरीके से हालात बदलते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को अचानक से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। उधर बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन विच्छेद हो गया। वहीं तेजी से बदले घटनाक्रम में मनोहर लाल के स्थान पर दलित चेहरा नयाब सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। शाम 5 बजे दलित ओबीसी समाज के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की गवर्नर ने शपथ दिलाई। उनके साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जय प्रकाश दलाल, डॉ. बनवारी लाल, कुंवरपाल है। जातिगत समीकरण के तहत एक स्वर्ण, एक दलित, 3 जाट, और एक गुर्जर समाज से हैं। सभी बनाए गए मंत्री खट्टर मंत्री मंडल में भी शामिल रहे हैं।पीछे की वजह में दरअसल जेजेपी ने लोकसभा के लिए ज्यादा सीटों की मांग की थी। इसपर बीजेपी तैयार नहीं थी। इसी बंटवारे पर असहमति के चलते जेजेपी और बीजेपी के अलग-अलग रास्ते हो गए।

सूत्रों की जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा के लिए लडाया जा सकता है। या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को हटाकर मनोहर लाल खट्टर को भाजपा अध्यक्ष पद की कमान सौपी जा सकती हैं। बता दें कि सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन अवसर में मौजूद मनोहर लाल खट्टर की पीएम नरेंद्र मोदी ने खासी बढाई की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि मनोहर लाल और हम दोनों बाइक पर हरियाणा मिशन के लिए घूमते रहते थे। हमने हरियाणा और पार्टी के लिए साथ-साथ बहुत काम किया है। और अगले ही दिन हरियाणा में सीएम खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। इधर बीजेपी से अलग हुए जेजेपी के 10 में से आधे विधायक बीजेपी के साथ पिंगे बढाने के लिए फिर बेताब हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बीजेपी की कुल सीट 41 निर्दलीय + 6 + एचएलपी1=48 वहीं कुल विधानसभा सीट हैं=90 बहुमत के लिए चाहिए:46 इस हिसाब से बीजेपी बहुमत में है। मंगलवार शाम 5 बजे बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की बागडोर थमा दी है। संजय भाटिया को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

शादी से पहले ब्यूटी पार्लर गई दुल्हन लापता, मंडप में इंतजार करते रहे घरवाले

गाजियाबाद के मोदीनगर के व्यक्ति के बेटे की शादी दिल्ली की एक युवती से तय हुई थी। इसके लिए मोदीनगर में ही एक बैंकट हॉल में बुक किया गया। दिल्ली से यहां परिवार समेत शादी के लिए आई थी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई। इससे पहले जो हुआ उससे दोनों पक्षों के घरवाले परेशान हो गए।

मोदीनगर। शादी से पहले मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर गई दुल्हन सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। वह दिल्ली से यहां परिवार समेत शादी के लिए आई थी। दुल्हन का मोबाइल भी बंद है। स्वजन को अनहोनी का डर सता रहा है।

दिल्ली की लड़की से तय हुई थी शादी

पुलिस शिकायत के आधार पर तलाश में जुट गई है। मोदीनगर की एक कॉलोनी के व्यक्ति के बेटे की शादी दिल्ली की एक युवती से तय हुई थी। दोनों पक्षों के बीच मोदीनगर में ही शादी समारोह करने पर सहमति बनी। मोदीनगर के एक बैंकट हॉल को बुक किया गया।

रविवार को ही दुल्हन पक्ष के लोग मोदीनगर आ गए। सोमवार रात करीब दस बजे दुल्हन मेकअप कराने के लिए निकली, लेकिन शाम तक नहीं लौटी। उसका मोबाइल भी बंद हो गया। स्वजन ने काफी तलाश की। उसके दोस्तों से भी पता किया।

दुल्हन का नहीं चल सका पता

हालांकि, उसका कोई सुराग नहीं लगा। खबर लिखने जाने तक दुल्हन का कोई सुराग नहीं लगा। स्वजन ने थाने में शिकायत दी। एसीपी ने बताया कि टीमें पुलिस की तलाश में जुटी है। जल्द उसकी सकुशल बरामदगी होगी।

युवती से शादी के बहाने दुष्कर्म

वहीं, इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र की एक युवती से युवक ने शादी का झांसा देकर दो साल तक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो मारपीट कर धमकी दी। पीड़िता ने इंदिरापुरम कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

एक साथ 4 लोगों का हुआ था मर्डर, सामूहिक नरसंहार के दोषी को हुई फांसी की सजा

गाजियाबाद। लोनी के टोली मोहल्ला में सामूहिक नरसंहार को अंजाम देने वाले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 पवन कुमार द्वितीय की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पौने तीन साल पहले 10 लाख रुपये उधार न देने पर दोषी ने ताऊ, ताई और दो तहेरे भाइयों की हत्या को अंजाम दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश त्यागी ने बताया कि लोनी थानाक्षेत्र के टोली मोहल्ले में कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन परिवार के साथ रहते थे। 27 जून 2021 की रात साढ़े 10 बजे भतीजा अय्यूब उनके घर अय्यूब आया और 10 लाख रुपये उधार मांगे। रईसुद्दीन ने पैसे उधार देने से मना कर दिया। इसके बाद अय्यूब रात में उनके घर ही रूक गया। उधार पैसे न देने से नाराज अय्यूब ने देर रात करीब ढाई बजे पहले ताऊ रईसुद्दीन को एक गोली मारी।

सीएम मनोहर ने पीएम मोदी को दिया ये भरोसा और हरियाणा में जजपा के साथ हो गया 'खेला'; टूट गया गठबंधन

परिवहन विशेष न्यूज

सोमवार को गुरुग्राम में पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करते हुए जिस तरह सीएम मनोहर लाल की तारीफ की थी और फिर मुख्यमंत्री ने जैसे पीएम को एक भरोसा दिलाया था उसके बाद रातों-रात हरियाणा सरकार में खेला हो गया। एक ओर जहां भाजपा ने गठबंधन से किनारा कर लिया वहीं सीएम ने गठबंधन की सरकार से इस्तीफा दे दिया। जानिए इसे पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह।

गुरुग्राम। सोमवार को गुरुग्राम पहुंचकर प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के दौरान सीएम मनोहर लाल के कामकाज की तारीफ क्या की, शाम होते-होते ही राज्य में बड़ा खेला हो गया।

साल 2019 में जजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को ही गच्चा दे दिया। पहले तो सोमवार रात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य मंत्रिमंडल की अनौपचारिका बैठक बुला ली। इसके बाद मंगलवार सुबह उन्होंने इस्तीफा दे डाला।

इस इस्तीफे के पीछे की वजह सिर्फ एक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सीएम मनोहर ने इस्तीफा गठबंधन की सरकार से दिया है और वह खुद शाम 4.00 बजे तक दोबारा शपथग्रहण करेंगे।

क्या है जजपा से गठबंधन तोड़ने की असल वजह

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन मौके पर राज्य के 2.82 करोड़ लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार मोदी की गारंटी तो पूरा करेगी ही साथ ही साथ राज्य की सभी 10 लोकसभा सीट जीतकर भी प्रधानमंत्री की झोली में डाल देगी।

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस भरोसे से आलाकमान भी आश्वस्त है और इसलिए उन्होंने जजपा से गठबंधन तोड़कर सभी 10 लोकसभा सीट पर कमल के निशान पर चुनाव लड़ने की ठानी है।

राजनीतिक निर्णय है मनोहर कैबिनेट का इस्तीफा

2019 में भाजपा ने राज्य में मनोहर लाल के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। तब भाजपा को 90 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीट मिली थी।

दुष्यंत चौटाला सहित जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक बने थे। छह निर्दलीय विधायक बने थे। भाजपा चाहती तो छह निर्दलीयों के साथ तब सरकार बना सकती थी लेकिन सरकार के स्थायित्व के चलते जजपा के साथ गठबंधन की सरकार बनाई।

मोदी की गारंटी की लहर के चलते लिया ये फैसला

अब लोकसभा चुनाव में भाजपा मोदी की गारंटी की लहर के चलते राज्य की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला ले चुकी है। गठबंधन दल होने के नाते जजपा के लिए दुष्यंत चौटाला दो सीट की मांग कर रहे थे लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य भाजपा नेताओं के आग्रह पर यह मांग ठुकरा दी।

इसके चलते दुष्यंत चौटाला के सामने अब स्वयं सहित जजपा के दो अन्य मंत्रियों देवेंद्र बबली और अनूप धानक के साथ सरकार से इस्तीफा देने का विकल्प था, लेकिन दुष्यंत ने इसमें देरी की।

इसके बाद मनोहर लाल जजपा मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते थे, लेकिन भाजपा ने राजनीतिक रूप से यह निर्णय लिया कि पूरी सरकार का इस्तीफा दिया जाए।

नीतीश कुमार की राह चले मनोहर लाल

मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट का इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। अब मनोहर लाल दोबारा भाजपा व अन्य समान विचार वाले विधायकों के समर्थन के साथ चुने हुए विधायक दल के नेता के नाते दोबारा शाम चार बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में नीतिश कुमार ने ऐसे ही दो बार किया है।

और क्या बोले थे पीएम से सीएम...

मुख्यमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए हरियाणा खास है। एक माह में प्रधानमंत्री राज्य की जनता के आग्रह पर दूसरी बार प्रदेश में आए हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने देशव्यापी अभियानों में सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन की शुरूआत हरियाणा से की थी। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी हरियाणा से शुरूआत की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज खुशी का दिन है क्योंकि उन्होंने मांग की थी जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए एक और एक्सप्रेस वे बनाया जाए। इसके बनने से गुरुग्राम सहित उत्तर भारत के जिन लोगों को भी एयरपोर्ट जाना हो, सफर आसान हुआ है।

केएमपी और केजीपी का लाभ हमें मिल रहा है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व ढांचागत संसाधनों का विकास हुआ है। विकास के साथ भगवान के राम के भव्य मंदिर के निर्माण से देश की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान मिली है।

आधे गुरुग्राम में 24 घंटे तक जल आपूर्ति रहेगी बाधित, शहर के इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंचेगा पानी

लगभग आधे शहर में 24 घंटे के लिए पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा चंदू बुढ़ेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रखरखाव का काम किया जाना है जिसमें वाल्व और नान-रिटर्न वाल्व (एनआरवी) को बदला जाएगा। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस-वे (Dwarka Expressway) पर मास्टर जल आपूर्ति पाइपलाइन की शिफ्टिंग का कार्य भी प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

गुरुग्राम। लगभग आधे शहर में 24 घंटे के लिए पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा चंदू बुढ़ेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रखरखाव का काम किया जाना है जिसमें वाल्व और नान-रिटर्न वाल्व (एनआरवी) को बदला जाएगा।

इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस-वे (Dwarka Expressway) पर मास्टर जल आपूर्ति पाइपलाइन की शिफ्टिंग का कार्य भी प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। इन दोनों कार्यों के लिए बुधवार सुबह दस बजे से बृहस्पतिवार सुबह दस बजे तक चंदू बुढ़ेड़ा प्लांट से शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बंद किया जाएगा।

इन क्षेत्रों में नहीं होगी पानी की सप्लाई

इस अवधि के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सेक्टर चार, पांच, सात, नौ, 11, 12, 81 से 115, दयानंद कालोनी, पुराना गुरुग्राम, लक्ष्मण विहार, छोटी माता बूस्टर और बूस्टिंग स्टेशन सेक्टर 51 (सेक्टर 42 से सेक्टर 74 तक और गांव बादशाहपुर) शामिल हैं। प्राधिकरण ने क्षेत्र के सभी निवासियों से अनुरोध किया है कि शटडाउन अवधि के दौरान पानी के संकट से से बचने के लिए पानी का उपयोग सही तरीके से करें।

गाजियाबाद में GDA का बुलडोजर एक्शन, आठ करोड़ की जमीन हुई कब्जामुक्त; विरोध पर पुलिस की सख्ती

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 20 साल से गौशाला के नाम पर कब्जा की हुई जमीन पर जीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जीडीए की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई करके आठ करोड़ की भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। कार्रवाई का कई लोगों ने विरोध भी किया हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे उन लोगों की एक भी न चली।

इंदिरापुरम। न्याय खंड एक में जीडीए ने मंगलवार को आठ करोड़ की भूमि को कब्जामुक्त कराया। इस भूमि पर गोशाला चलाने की आड़ में 20 साल से कब्जा किया हुआ था। बुलडोजर चलने का कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सभी शांत हो गए।

गौशाला के नाम पर था कब्जा

जीडीए की 400 वर्ग मीटर भूमि खाली थी। इस भूमि पर गोशाला चल रही थी। गोशाला चलाकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था। काफी दिन से लोग अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे थे। गोशाला का गोबर खुले में फेंका जा रहा था। जीडीए ने गोशाला संचालक को पूर्व में कई बार नोटिस दिया गया था।

इसके बाद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मंगलवार को जीडीए की टीम मौके पर पहुंची। संचालक ने बुलडोजर चलाने पर उसके आगे लेटने की चेतावनी दी। जीडीए ने उसकी चेतावनी को दरकिनार करते हुए अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। सभी गोवंशी को संचालक को सौंप दिए।

विरोध पर पुलिस की चेतावनी

जीडीए के सहायक अभियंता पीयूष सिंह ने बताया कि जब भी पूर्व में वह कार्रवाई करने गए तो महिलाओं को आगे कर दिया जाता था। जिस वजह से पूर्व में कई बार कार्रवाई को रोका गया था। इस बार भी कार्रवाई रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने की चेतावनी दी तो वह शांत हो गया।

कांग्रेस से हो रहे पलायन को सिर्फ देखते रहने के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टी के आला नेता?

ललित गर्ग

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को रोज एक न एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दें पता नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है, उसी समय से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू हो जाता है।

कांग्रेस के दिग्गज एवं कद्दावर नेताओं में नाराजगी, हताशा एवं राजनीतिक नेतृत्व को लेकर निराशा के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, पार्टी लगातार बिखराव एवं टूटन की ओर बढ़ रही है। पार्टी में उल्टी गिनती चल रहा है, लेकिन आश्चर्य इस बात को लेकर है कि इस उल्टी गिनती को रोकने के लिए कोई मजबूत उपाय नहीं हो रहे हैं। पार्टी से एक के बाद एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस का दामन छोड़ने में लगे हुए हैं, कांग्रेस छोड़ने वाले इन नेताओं में कुछ राहुल गांधी के खास रहे हैं तो कुछ सोनिया गांधी के। पहले कांग्रेस में गिनती वन, टू, थ्री से होती थी। आजकल थ्री, टू, वन से होती है। पार्टी को मजबूती देने एवं पार्टी छोड़ कर जाने वाले नेताओं को रोकने की गिनती कौन शुरू करेगा? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले देश में एकता यात्रा और उसके बाद अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन वे पार्टी के भीतरी असंतोष एवं निराशा को रोकने का अभियान क्यों नहीं शुरू करते? क्या गांधी परिवार का अहंकार एवं परिवारवादी सोच ही पार्टी के टूटने का कारण है?

आगामी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बीते कुछ समय से शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो, जब किसी कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने की खबर न आयी हो। गत दिवस गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी एवं पूर्व कांग्रेसी सांसद गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी समेत मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसके पहले गुजरात, असम, महाराष्ट्र और यहां तक कि केरल के भी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। एक के बाद एक नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला यही बताता है कि उन्हें पार्टी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, पार्टी नेतृत्व की अपरिपक्व एवं बचकाना राजनीति एवं देश-विकास की कोई स्पष्ट नीति न होना भी इन नेताओं के पार्टी छोड़ने का कारण है। राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा के खिलाफ कोई मजबूत विरोधी दावे नहीं हैं, चुनाव जीतने के लिये जिस तरह की राजनीति सोच एवं एजेंडा होना चाहिए, वह भी दिखाई नहीं दे रहा है। जातीय जनगणना, अदाणी- अंबानी, युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों की अनदेखी करने के खोखले एवं बेबुनियाद आरोप के अलावा और कुछ कहने को नहीं है। वे जिन समस्याएं की चर्चा करते हैं, उनका कोई कारगर समाधान उनके पास नहीं हैं। अक्सर वे समाजवादी और वामपंथी नीतियों की वकालत करते दिखते हैं, जो पहले ही नाकाम हो चुकी हैं। कांग्रेस की यह विडम्बनापूर्ण एवं बेजान स्थिति तब है, जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है। कांग्रेस से लगातार पलायन करते नेताओं की यह दर्दनाक स्थिति रेखांकित करती है कि पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं को प्रेरित एवं रोक नहीं कर पा रहा है। इसके लिए सबसे अधिक दोषी राहुल गांधी और उनके इर्द-गिर्द के लोग हैं, जो भाजपा एवं मोदी सरकार को चुनौती देने के नाम पर घिसे-पिटे बयान देने में लगे हुए हैं।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को रोज एक न एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दें पता नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है, उसी समय से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटक, सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में शामिल रहे दिग्गज भी अब भाजपा के साथ हैं तो वहीं कांग्रेस में सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं में से रीता बहुगुणा जोशी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आजाद भी बहुत पहले ही पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। कांग्रेस से युवा नेताओं का भी मोह भंग होता जा रहा है। इसका उदाहरण मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर जैसे नेता हैं, जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। बिहार में अशोक चौधरी, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सुनील जाखड़ के साथ अश्वनी कुमार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हान जैसे भी नेता हैं जो पार्टी के काम करने के तरीके से नाखुश होकर पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। ये वे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने पहचान दी, केन्द्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री बनाया, पार्टी में बड़े पदों पर बिठाया परन्तु पार्टी के मुश्किल वक्त में वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं।

कांग्रेस के दिग्गज नेता जो पार्टी छोड़ चुके या छोड़ने की फिराक में है, वे नरेन्द्र मोदी एवं राहुल के बीच के फर्क को महसूस कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता यह गहराई से देख रहे हैं कि राहुल किस तरह हमारे सैनिकों की वीरता-शौर्य-बलिदान पर सवाल उठाते रहे हैं, भारत की बढ़ती साख, सुरक्षा एवं विकास की तस्वीर को बट्टा लगाते हैं। इन नेताओं ने महसूस किया कि किन्हीं राहुल रूपी गलतबयानी की वजह से मोदी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है, भारत ही नहीं, समूची दुनिया में मोदी के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा का भाव निरन्तर प्रवर्द्धमान है। राहुल गांधी एवं उनके रणनीतिकारों की नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार के प्रति शाश्वत वैर-भाव एवं विरोध की राजनीति समझ में आती है लेकिन देश की छवि खराब करने, सरकार को कमजोर बता कर और मोदी जैसे कद्दावर नेता को खलनायक बनाने से उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी। यह तो विरोध की हद है! नासमझी एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का शिखर है!! उजालों पर कालिख पोतने के प्रयास हैं!!! इसकी कीमत कांग्रेस पार्टी अपने कद्दावर नेताओं को खोकर दे रही है।

> “ कांग्रेस के दिग्गज नेता जो पार्टी छोड़ चुके या छोड़ने की फिराक में है, वे नरेन्द्र मोदी एवं राहुल के बीच के फर्क को महसूस कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता यह गहराई से देख रहे हैं कि राहुल किस तरह हमारे सैनिकों की वीरता-शौर्य-बलिदान पर सवाल उठाते रहे हैं, भारत की बढ़ती साख, सुरक्षा एवं विकास की तस्वीर को बट्टा लगाते हैं। इन नेताओं ने महसूस किया कि किन्हीं राहुल रूपी गलतबयानी की वजह से मोदी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है, भारत ही नहीं, समूची दुनिया में मोदी के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा का भाव निरन्तर प्रवर्द्धमान है।

दरअसल भाजपा के ताकतवर होने के बाद कांग्रेस ने कभी भी पार्टी के लगातार कमजोर पड़ते जाने को लेकर आत्मंथन नहीं किया। कांग्रेस नीति और सिद्धांत भी संदेहास्पद होते चले गये हैं। ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस के मजबूत किले में तोडफ़ोड़ करने में कसर बाकी नहीं रखी। भाजपा ने दोतरफ से कांग्रेस का घेराव किया। एक तरफ कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को न सिर्फ उजागर किया बल्कि कई दिग्गजों पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई भी करवाई। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस में सेंधमारी करके उसके मजबूत नेताओं को तोड़ा और पार्टी को हाशिए पर ले आयी। दोनों तरफ से पिटती कांग्रेस में नेताओं को लगने लगा कि इसके दिन लद गए लगते हैं, यहां उनका राजनीतिक जीवन अंधकारमय है।

राहुल गांधी अपने आधे-अधूरे, तथ्यहीन एवं विध्वंसात्मक बयानों को लेकर निरन्तर चर्चा में रहते हैं। उनके बयान हास्यास्पद होने के साथ उद्देश्यहीन एवं उच्छृंखल भी होते हैं। राहुल ने पहले भी बातों-बातों में मोदी विरोध के नाम पर राष्ट्र-विरोध किया है। वह देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं। सरकार की नीतियों से नाराज होना, सरकार के कदमों पर सवाल उठाना उनके लिए जरूरी है। राजनीतिक रूप से यह उनका कर्तव्य भी है। लेकिन उनके विरोध एवं राजनीति में वह दम-खम नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके। यही बात कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो हलचल है उसका एक बड़ा कारण है। वैसे कांग्रेस की अंतर्कलह की वजहें काफी सालों से हैं जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खरगे तक रोकने में असक्षम दिख रहे हैं। भले ही कांग्रेस के कुछ चाटुकार नेता पार्टी से पलायन का कारण केन्द्रीय एजेंसियों का दबाव और इसे ही भाजपा में जाने का कारण बतायें। अगर कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व इतना प्रभावी एवं सक्षम होता तो वे अपने जाने वाले नेताओं को रोकते हुए कहते कि ये वक्त किसी दबाव के आगे झुकने का नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने और देश के भविष्य के लिए संघर्ष करने का है। कांग्रेस तो इतनी जर्जर एवं आधारहीन हो गयी है कि उसने पूरे देश में विपक्ष को एनडीए के खिलाफ इकठ्ठा करने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया, तब उसे लगा था कि देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए यह रास्ता आसान होगा। लेकिन, एक-एक कर इंडिया गठबंधन से पार्टियां अलग होती चली गईं। सबसे पहले नीतीश कुमार जिन्होंने इस गठबंधन के लिए सबको इकट्ठा किया था भाजपा के साथ हो लिए। फिर ममता बनर्जी को भी कांग्रेस का साथ रास नहीं आया। इसके मायने तो यही हैं कि कांग्रेस खुद की पार्टी एवं इंडिया गठबंधन को संभालने में ही नाकाम रही तो वह देश क्या संभालेगी?

Porsche ने पेश की अपनी सबसे तेज और पावरफुल कार, केवल 4.5 सेकेंड में पकड़ेगी 0 से 100 KMPH की रफ्तार

Porsche Taycan Turbo GT में कार्बन सिरेमिक ब्रेक और 21 इंच के फोर्ज्ड व्हील्स हैं जो टर्बो एस की तुलना में हल्के हैं। पहिए पिरेली पी जीरो ट्रोफियो आर टायर के साथ लिपटे हुए हैं। इसमें स्पेसिफिक ट्यूनिंग के साथ स्टैंडर्ड रूप में पोर्श का एक्टिव राइड सस्पेंशन मिलता है। आइए Porsche की इस नवीनतम पेशकश के बारे में जान लेते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। Porsche ने Tayca Turbo GT को पेश किया है। आपको बता दें कि ये जर्मन स्पोर्ट्सकार मार्के की अब तक की सबसे फास्ट और शक्तिशाली कार है। दिलचस्प बात यह है कि Porsche Taycan का बेस वेरिएंट भी केवल 4.5 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सक्षम है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Porsche Taycan Turbo GT में क्या खास?

पोर्शे टायकन टर्बो जीटी में कार्बन सिरेमिक ब्रेक और 21 इंच के फोर्ज्ड व्हील्स हैं, जो टर्बो एस की तुलना में हल्के हैं। पहिए पिरेली पी जीरो ट्रोफियो आर टायर के साथ लिपटे हुए हैं। इसमें स्पेसिफिक ट्यूनिंग के साथ स्टैंडर्ड रूप में पोर्श का एक्टिव राइड सस्पेंशन मिलता है, जबकि एयरो ब्लेड के साथ एक नया फ्रंट स्पॉइलर और एडेप्टिव रियर स्पॉइलर के ऊपर एक फ्लैप भी इस ईवी के लिए स्टैंडर्ड है। इसके अलावा Taycan Turbo GT को एक अंडरबॉडी एयर डिफ्लेक्टर और नया फ्रंट डिफ्यूजर दिया गया है।

इंजन और परफॉरमेंस

Taycan Turbo GT टर्बो एस वेरिएंट की तुलना में केवल 2.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंचने का वादा करती है। पॉर्श टायकन टर्बो जीटी ऑटोमेकर द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे शक्तिशाली कार भी है।

ये स्टैंडर्ड रूप में 766 बीएचपी पीक पावर का वादा करती है, जिसे नए अटैक मोड फंक्शन के साथ 1,005 बीएचपी तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, Taycan Turbo GT 1,344 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है। ये इलेक्ट्रिक मीन मशीन 305 किमी प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है।

2024 Renault Duster के बाद कंपनी की ये धांसू SUV भी मारेगी एंट्री? Safari और XUV700 की बढ़ेगी मुश्किल

Renault Bigster का टेस्टिंग म्यूल कैमोफ्लैग से ढका हुआ था लेकिन कुछ डिजाइन एलीमेंट सामने आए हैं। नई पीढ़ी की रेनो डस्टर से संकेत लेते हुए डेसिया की ये एसयूवी लगभग समान डिजाइन और बेहतरीन स्पेस के साथ आएगी। इसके अलावा इसकी बढ़ी हुई बैठने की क्षमता को समायोजित करने के लिए इसे एक बड़ी संरचना मिलेगी जिसकी लंबाई 4.6 मीटर होने की संभावना है।

नई दिल्ली। नई Renault Duster के ग्लोबली अनवील किए जाने के बाद कंपनी एक नई 7-सीटर एसयूवी पर काम कर रही है। आपको बता दें कि इसे बिगस्टर के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल को हाल ही में पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

डिजाइन और डायमेंशन

Renault Bigster का टेस्टिंग म्यूल कैमोफ्लैग से ढका हुआ था, लेकिन कुछ डिजाइन एलीमेंट सामने आए हैं। नई पीढ़ी की रेनो डस्टर से संकेत लेते हुए डेसिया की ये एसयूवी लगभग समान डिजाइन और बेहतरीन स्पेस के साथ आएगी।

इसके अलावा, इसकी बढ़ी हुई बैठने की क्षमता को समायोजित करने के लिए इसे एक बड़ी संरचना मिलेगी, जिसकी लंबाई 4.6 मीटर होने की संभावना है।

इंजन ऑप्शन

पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो, ये अनुमान लगाया गया है कि बिगस्टर नवीनतम पीढ़ी के डस्टर से समान पावरट्रेन उधार लेगी, जो दो हाइब्रिड विकल्पों सहित तीन इंजन विकल्प प्रदान करती है। उम्मीद है कि रेनो इस मॉडल के लिए 1.6-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड या 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश करेगा।

लॉन्च टाइमलाइन

Renault Duster को 2025 की दूसरी छमाही में पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद संभवतः Bigster को लॉन्च किया जाएगा। भारत में यह मॉडल सीधे तौर पर Tata Safari और Mahindra XUV700 जैसी कारों को टक्कर देगी।

IIEV Expo 15 मार्च से यशोभूमि में होगा आयोजित, 10 देशों की 150 से अधिक कंपनियां ले रही हैं हिस्सा

India International EV expo का चौथा संस्करण यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। मुकेश यादव ने कहा कि भाग लेने वालों में ईवी निर्माता बैटरी कंपनियां चार्जिंग स्टेशन एप्लिकेशन कंपनियां और अन्य शामिल होंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन ईको-सिस्टम का हिस्सा हैं। Futurex ने इससे पहले चेन्नई में और दो बार पुणे में एक्सपो का आयोजन किया था। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Futurex Group द्वारा 15 मार्च से शुरू होने वाले तीन दिवसीय India International EV expo में 150 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं। आपको बता दें कि IIEV Expo का ये चौथा एडिशन है।

इंडिया इंटरनेशनल ईवी (आईआईईवी) एक्सपो का चौथा संस्करण यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा।

इसको लेकर फ्यूचरएक्स के परियोजना प्रमुख मुकेश यादव ने कहा-

भारत अंतर्राष्ट्रीय ईवी एक्सपो में 10 देशों के 150 से अधिक प्रदर्शक होंगे। यह एक्सपो का चौथा संस्करण है और दिल्ली में पहला है। इस वर्ष प्रदर्शकों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ये कंपनियां लेंगी हिस्सी

मुकेश यादव ने कहा कि भाग लेने वालों में ईवी निर्माता, बैटरी कंपनियां, चार्जिंग स्टेशन, एप्लिकेशन कंपनियां और अन्य शामिल होंगे, जो इलेक्ट्रिक वाहन ईको-सिस्टम का हिस्सा हैं। Futurex ने इससे पहले चेन्नई में और दो बार पुणे में एक्सपो का आयोजन किया था।

Ather Community Day में Rizta ई-स्कूटर के साथ पेश की जाएगी हाई टेक एक्सेसरी, Tarun Mehta ने खुद बताया

Tarun Mehta ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि हेलो एक टॉप-सीक्रेट एक्सेसरी है जिसका खुलासा 6 अप्रैल को एथर कम्युनिटी डे 2024 में किया जाएगा। उन्होंने यह भी लिखा कि एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर के मालिक जो ग्राउंड पर इवेंट में शामिल होंगे उन्हें ये एक्सेसरी जीतने का मौका भी मिल सकता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Ather Energy ने हाल ही में Hello नाम की एक नई एक्सेसरी को टीज किया है। कंपनी इसे 6 अप्रैल को होने वाले Ather Community Day पर लॉन्च करेगी। ईवी स्टार्टअप के सीईओ Tarun Mehta ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर आगामी स्मार्ट एक्सेसरी पहली झलक पेश की है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

तरुन मेहता ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि हेलो एक टॉप-सीक्रेट एक्सेसरी है, जिसका खुलासा 6 अप्रैल को एथर कम्युनिटी डे 2024 में किया जाएगा। उन्होंने यह भी लिखा कि एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर के मालिक जो ग्राउंड पर इवेंट में शामिल होंगे, उन्हें ये एक्सेसरी जीतने का मौका भी मिल सकता है।

Ather Halo क्या है?

Ather Halo ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स वाला एक स्मार्ट हेलमेट हो सकता है। उम्मीद है कि फीचर्स के साथ हेलमेट को यूजर्स के स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकेगा। इनमें नेविगेशन डायरेक्शन, स्पीड और बैटरी लेवल जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि, ईवी स्टार्टअप ने इसको लेकर कोई खास जानकारी नहीं साझा की है।

Ather Rizta भी है तैयार

एथर एनर्जी अपने अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर रिज्टा को भी प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, जो एक बजट-फ्रेंडली और फैमिली स्कूटर होने वाला है। ओईएम ने पहले ही कई मौकों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिज्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर को टीज किया है, जिसमें स्कूटर की सीट को काफी हाईलाइट किया गया है। उम्मीद है कि इसे नए प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा और इसमें नया इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक भी होगा।

किसानों के लिए सरकार की अहम पहल

डा. जयंती लाल भंडारी
विख्यात अर्थशास्त्री

निश्चित रूप से इस समय जब भारत 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, देश में अभी भी 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और भारत को कुपोषण की समस्या से ग्रसित देश के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, तब भारत में खाद्य सुरक्षा, अधिक खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न भंडारण की जरूरत बनी हुई है।

हम उम्मीद करें कि हाल ही में डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में जिस तरह भारत ने खाद्य सुरक्षा व एमएसपी का मुद्दा प्रभावी तरीके से उठाया है, उससे दुनिया के अन्य देशों का समर्थन बढ़ेगा और इसका स्थायी समाधान होगा। साथ ही हाल ही में लांच की गई बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना से लाभ मिलेगा'

एक ओर जब इन दिनों देश में किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित में उठाई गई दो महत्वपूर्ण पहलें दुनियाभर में रेखांकित हो रही हैं। एक, हाल ही में भारत के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबूधाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी पहल की गई, जिसके कारण इस सम्मेलन में इन मुद्दों पर कई विकसित देश भारत के किसानों के हितों के प्रतिकूल कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा पाए। ऐसे में अब भी भारत अपने किसानों के उपयुक्त लाभ के लिए नीतियां बनाने में सक्षम है। दो, 24 फरवरी को सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए प्रायोगिक परियोजना लांच की है। यह प्रायोगिक परियोजना 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को लक्षित कर रही है, जिनके माध्यम से पैक्स की किसानों के हित में बहुआयामी भूमिका होगी।

गौरतलब है कि कृषि पर अबूधाबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने जी-33 देशों के समूह, अफ्रीकी देशों और प्रशांत देशों के समूह की आवाज के साथ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग (पीएचएस) के स्थायी समाधान को अंतिम रूप देने के लिए मजबूती से पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब डब्ल्यूटीओ को केवल निर्यातक देशों के व्यापारिक हितों तक ही अपना ध्यान सीमित नहीं रखना चाहिए, असली चिंता दुनिया के करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका की होनी चाहिए। वस्तुतः खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक भंडारण के लिए भारत सरकार गेहूं और चावल मोटे अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की पहले से तय कीमत पर खरीदती है और फिर उन्हें गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सस्ते दाम या मुफ्त में वितरित करती है। यह खाद्य सुरक्षा भूख से त्रस्त लाखों लोगों को भूख से बचाने का सरकार का नीतिगत तरीका है। यह भारत के द्वारा वर्ष 2030 तक देश में भूख व गरीबी मिटाने के लक्ष्य से जुड़ा मुद्दा भी है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक 1986-88 के मूल्यों को आधार मानते हुए उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। भारत इसमें बदलाव चाहता है ताकि किसानों को अधिक सब्सिडी देने पर वैश्विक मंच पर उसका विरोध नहीं हो सके। अमरीका सहित कई विकसित राष्ट्र खाद्यान्न के लिए भारत में दिए जा रहे एमएसपी कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि इस पर दी जा रही सब्सिडी डब्ल्यूटीओ व्यापार नियमों के तहत स्वीकृत सीमा से करीब तिगुनी हो गई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2013 में बाली में हुए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सार्वजनिक भंडारण और खाद्य सुरक्षा को लेकर एक पीस क्लॉज पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके तहत अन्न भंडारण कार्यक्रम का स्थायी हल नहीं निकलने तक किसी भी देश के द्वारा अनाज की खरीददारी और उसे कम दाम पर लोगों को देने का विरोध नहीं किया जाएगा। भारत को आशंका है कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर रोक लगाई जाएगी तो इससे देश के करोड़ों लोगों की भूख, करोड़ों किसानों की आजीविका और भारतीय कृषि के भविष्य पर असर पड़ सकता है। इसी कारण भारत खाद्य सब्सिडी की सीमा तय करने का फॉर्मूला बदलने की मांग कर रहा है।

निश्चित रूप से इस समय जब भारत 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, देश में अभी भी 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और भारत को कुपोषण की समस्या से ग्रसित देश के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, तब भारत में खाद्य सुरक्षा, अधिक खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यन्न भंडारण की जरूरत बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार के सराहनीय प्रयास दिखाई भी दे रहे हैं। जहां सरकार डब्ल्यूटीओ सहित अन्य वैश्विक मंचों पर किसानों को अधिक समर्थन को न्यायसंगत बताती है, वहीं हाल ही में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लांच की गई दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत अगले पांच साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख टन अनाज की भंडारण क्षमता के हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि अब कम्प्यूटरीकृत पैक्स को गोदाम तैयार करने, कस्टर हायरिंग सेंटर बनाने, उचित मूल्य की दुकानों की प्रक्रिया में तथा प्रसंस्करण इकाइयां तैयार करने जैसी बहुआयामी भूमिका में शामिल किया गया है। नई खाद्यान्न भंडार योजना वस्तुतः देश में भंडारण के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नई विशाल भंडारण क्षमता के बाद किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण प्राप्त करने और बाजार मूल्य लाभकारी होने पर अपने खाद्यान्न को बेचने में सक्षम होंगे।

नई खाद्यान्न भंडार योजना का मकसद देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, भंडारण क्षमता में कमी के कारण किसानों को फसल पैदावार के मौसम में कम मूल्य पर की जाने वाली बिक्री से होने वाले नुकसान से बचाना भी है। इस समय देश का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 3200 लाख टन से भी अधिक है, जबकि भंडारण क्षमता कुल उत्पादन का केवल 47 प्रतिशत ही है। ऐसे में निश्चित रूप से तेजी से बढ़ता हुआ खाद्यान्न उत्पादन अब किसानों के परम्परागत खाद्यान्न भंडारों और सरकार की खाद्यान्न संग्रहण क्षमताओं को लांघते हुए चुनौतीपूर्ण बन गया है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि पिछले एक दशक में सरकार के विभिन्न कृषि योजनाओं के द्वारा छोटे किसानों और कृषि विकास को जिस तरह समर्थन मिला है, उससे कृषि उत्पादन लगातार बढ़ता गया है और खाद्यान्न भंडारण की आवश्यकता बढ़ती गई है। यद्यपि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है, लेकिन खाद्यान्न भंडारण में अभी भी बहुत पीछे है।

अनाज के अन्य बड़े उत्पादक देशों चीन, अमरीका, ब्राजील, यूक्रेन, रूस और अर्जेन्टीना के पास खाद्यान्न भंडारण क्षमता वार्षिक उत्पादन की मात्रा से कहीं अधिक है। ऐसे में नई खाद्यान्न भंडार योजना के माध्यम से देश में खाद्यान्न भंडारण की जो क्षमता फिलहाल 1450 लाख टन की है, उसे अगले 5 साल में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करके कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 2150 लाख टन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि इस योजना के क्रियान्वयन में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) अहम भूमिका होगी। अतः पैक्स तथा सरकार के बीच उपयुक्त तालमेल जरूरी होगा। देश में अभी करीब एक लाख पैक्स हैं। पैक्स की क्षमता में सुधार करना होगा। पैक्स के स्तर पर भंडार गृह, प्रसंस्करण इकाई आदि कृषि व्यवस्थाएं निर्मित करके पैक्स को बहुउद्देशीय बनाए जाने के लिए उच्च स्तर पर खाद्यान्न भंडारण में विविधता लाई जाना होगी। हम उम्मीद करें कि हाल ही में डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में जिस तरह भारत ने खाद्य सुरक्षा व एमएसपी का मुद्दा प्रभावी तरीके से उठाया है, उससे दुनिया के अन्य देशों का समर्थन बढ़ेगा और इसका स्थायी समाधान होगा। साथ ही सरकार के द्वारा हाल ही में लांच की गई सहकारी क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना किसानों की खुशहाली, देश के कृषि विकास व अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

संपादक की कलम से

हिमाचल में रेल के सपने

अंब-अंदौरा के बाद एक और वंदे भारत ट्रेन हिमाचल के नजदीक पहुंच रही है। दरअसल वैष्णो देवी दौड़ रही वंदे भारत अब पठानकोट कैंट में रुकेगी, तो पंख फैलाए हिमाचल को दूर से ही सही इसमें बैठने का मौका मिल जाएगा। हम इसमें भी खुश हैं कि पठानकोट से ही देश के साथ कदमताल का अवसर मिल गया, वरना सपनों की ट्रेन तो आज भी कम चौड़ी पटरियों पर जगह तलाश रही है। वंदे भारत का पठानकोट में रुकना हिमाचल को कितना समृद्ध कर रहा है, इसको लेकर शाबाशियों और आत्म श£ाघा का एक दौर जरूर चलेगा, लेकिन हिमाचल की असली ट्रेन है कहां। अब अंब-अंदौरा की वंदेभारत ज्यादा व्यावहारिक होगी या पठानकोट कैंट की, इस पर यात्रीगण जरूर ध्यान देंगे, लेकिन राहत यह कि दिल्ली का सफर सीधा होने जा रहा है। पर्यटन और ट्रेन के बीच घनिष्ठता उन संभावनाओं को ढोती है, जो भविष्य की आर्थिकी का समाधान है। विडंबना यह है कि हिमाचल के आसपास जम्मू-कश्मीर की पटरियां बिछती गईं और हम अंग्रजों की विरासत में नैरो गेज ट्रेन के शहतीर बनकर धंसते गए। कम से कम कांगड़ा की तरफ तो रेलवे विस्तार की दिशा में सिर्फ यही खबर आई कि ब्रिटिश पीरियड में निर्मित बैजनाथ-पपरोला रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, वरना वही पटरियां और वही गति। बारिश की आपदा ने रोकी, तो महीनों रुक गई कांगड़ा घाटी की रेलगाड़ी। यह दीगर है कि बिलासपुर की ट्रेन करवट ले रही है और ऊना की पटरियां फैल रही हैं, लेकिन रेलवे का इतिहास कांगड़ा-मंडी और चंबा में शर्मिंदा है। ऐसे में वंदे भारत के नखरे में सवार होना भी गनीमत है, भले ही पठानकोट या अंब-अंदौरा पहुंचते-पहुंचते खासी मेहनत करनी पड़े।
बेशक वंदे भारत के दो विकल्प पर्यटन के रास्तों को सरल कर देंगे और अगर इनके साथ एचआरटीसी के रूट समाहित कर दें, तो दिल्ली से अंब-अंदौरा या अब पठानकोट से आगे डेस्टिनेशन टूरिज्म तक पहुंचना सुविधाजनक होगा। बावजूद इसके हिमाचल के हिस्से में भी कुछ पटरियां चाहिएं। पठानकोट से जोगिंद्रनगर की एक सदी पुरानी ट्रेन भले ही धरोहर बन जाए, लेकिन इसके आसपास कुछ तो निगाह चाहिए। हमारा मानना है और यही एक मात्र विकल्प साबित होगा कि अंब-अंदौरा तक पहुंची रेल लाइन का एक रुख ज्वालाजी मंदिर की ओर मोड़ दिया जाए। ज्वालाजी मंदिर तक ट्रेन का आना धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, क्रांतिकारी प्रयास होगा, क्योंकि इसके कारण चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, दियोटसिद्ध, कांगड़ा, चामुंडा व बैजनाथ तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। ज्वालाजी मंदिर तक रेलवे मार्ग बिछे तो इसे आसानी से कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और बिलासपुर की ओर बढ़ाया जा सकता है। आश्चर्य यह कि हिमाचल की प्राथमिकताएं कागजी नक्शों पर सियासत की अपनी-अपनी गोटियां फिट करके भविष्य की रूपरेखा को सुदृढ़ नहीं कर पातीं।
यह तय है कि पठानकोट से अब मंडी की ओर नई ब्रॉडगेज लाइन नहीं बिछेगी। यह इसलिए भी कि भानुपल्ली-बिलासपुर रेल मार्ग ही इस दृष्टि से आगे मंजिल देखेगा। ऐसे में अंब-अंदौरा से ज्वालाजी मंदिर रेल मार्ग को धार्मिक पर्यटन से जोडक़र देखना होगा। रेलवे के साथ फिफ्टी-फिफ्टी पार्टनरशिप पर मंदिर रेल परियोजना बनाकर हिमाचल कोंकण रेलवे की तरह आगे बढ़ सकता है। बहरहाल वंदे भारत ट्रेन का अंब अंदौरा तक आगमन हमीरपुर, ऊना व कांगड़ा के लिए सुखद अनुभव रहा है। ऐसे में वाया पठानकोट वंदे भारत ट्रेन के साथ हिमाचल का जुडऩा वरदान साबित होगा। इन दोनों ट्रेनों की क्षमता में हिमाचल की जनता को सुविधाजनक तरीके से जोडऩे के लिए एचआरटीसी को ऐसी बुकिंग व्यवस्था करनी चाहिए जो हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी व चंबा के यात्रियों को नियमित रूप से इन ट्रेनों से जोड़ दे। इसी तरह के प्रयास उड़ान के तहत धर्मशाला-शिमला हवाई यात्रा के साथ भी होने चाहिएं। खास तौर पर शिमला एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट्स को सफल बनाने के लिए एचआरटीसी ऐसी बस सेवाएं दे, जो यात्रियों की उड़ान की जमीनी स्तर तक पैरवी करे।

राय

समारोह पर्यटन की दृष्टि से

हिमाचल के सांस्कृतिक परिदृश्य की निरंतरता में मंडी शिवरात्रि समारोह का ही नजराना पेश हो, तो पर्यटन की मंडी में आर्थिकी का नया दौर शुरू हो सकता है। हम इन सांस्कृतिक समारोहों की रौनक में मंचीय उपलब्धियां देख रहे हैं, तो सियासत की पगडियों में सत्ता का नूर मुखातिब होता है। कुल्लू से मंडी तक के समारोहों में देवताओं या बजंतरियों का नजराना बढ़ाने की मशक्कत, सांस्कृतिक संरक्षण की पैरवी में यकीनन इजाफा करती है, लेकिन इस तरह का उजास पूरे हिमाचल को परिभाषित नहीं करता। हिमाचल में देव स्तुति की अनेक परंपराएं बिना किसी संरक्षण के समाप्त प्रायः हो रही हैं। उदाहरण के लिए ढोलरू गायन परंपरा का सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक पक्ष निरंतर घट रहा है, तो इसलिए कि सरकारी तौर पर इसे बचाने के प्रयास नहीं हो रहे। भाषा एवं संस्कृति विभाग इस तरह की परंपराओं का मंचीन संबोधन बढ़ा सकता है, लेकिन न तो कलाकारों को प्रश्रय मिला और न ही विशिष्ट महीने के दौरान सार्वजनिक मंच प्रदान करते हुए इनका स्वरूप बदला। क्यों नहीं ढोलरू गायकों को भी सरकार की ओर से वार्षिक नजराना दिया जाए ताकि यह कला बची रहे। इतना ही नहीं ढोलरू समारोहों की एक श्रृंखला विभिन्न मंदिरों के परिसर में शुरू की जाए, तो समाज भी खुद को इनके करीब रख पाएगा। कुछ अन्य लोक नाट्य परंपराएं भी समय के साथ परिदृश्य से गायब हो रही हैं।

ऐसे में अगर कुल्लू का दशहरा या मंडी की शिवरात्रि से जुड़े मंच हर साल नजरानों की पेशकश में सत्ता की सदाबहार चमक दिखाते हैं, तो इस तरह के वित्तीय प्रोत्साहन समूचे हिमाचल के प्रत्येक कलाकार को भी मिलने चाहिएं। हिमाचल में समारोह पर्यटन के जरिए आर्थिकी को समृद्ध करने के लिए जरूरी है कि आयोजनों के प्रारूप को बदला जाए। मंडी में शाही जलेब के पड्डल मैदान पर पहुंचते ही शोभा यात्रा का अशोभनीय पक्ष यह कि एक कांग्रेसी नेत्री के कपड़े फट गए। ऐसे में अगर बाहर से पर्यटक शरीक होना चाहें तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने क्या किया। ऐसे सांस्कृतिक समारोहों के लिए अब एक खास अधोसंरचना, सुरक्षा दायरे, अनुशासिक प्रक्रिया तथा अतिरिक्त मैदानों की जरूरत है। मंडी में शिवरात्रि, कुल्लू में दशहरा या चंबा में मिंजर की लोक परंपरा को वैश्विक परिदृश्य में सुव्यवस्थित तथा रोचक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है। बेशक सुक्खू सरकार ने कुछ मेलों व समारोहों को राज्यस्तरीय पोशाक पहना दी है, लेकिन इस तरह की श्रेष्ठता में हम क्या दिखाना चाहते हैं, इसके लिए नीति व प्रबंधन चाहिए। हमारा मानना है कि हिमाचल में एक मेला विकास प्राधिकरण के तहत ही तमाम सांस्कृतिक, धार्मिक व व्यापारिक मेलों का आयोजन करते हुए इन्हें पर्यटन समारोह भी बनाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि सुजानपुर, चंबा या रामपुर बुशहर की धरोहर व ऐतिहासिक महत्त्व को पर्यटन का स्तंभ बनाया जाए, तो प्रक्रिया, प्रोग्राम व प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करना होगा।

आम तौर पर ऐसे आयोजनों की कोई स्थायी वित्तीय व्यवस्था नहीं है, अतः प्राधिकरण के तहत आय-व्यय की जवाबदेही तय करनी होगी। हिमाचल की मेला संस्कृति में विविधता, रोमांच व पारंपरिक उल्लास के साथ-साथ अब ये कला, कलाकार, कुश्ती व व्यापार के संरक्षण में भूमिका निभा रहे हैं। अगर मेलों की कुश्तियों को पहलवानी के प्रशिक्षण के साथ जोड़ दें, तो हिमाचल का खेल ढांचा ग्रामीण खेलों को पुष्ट कर देगा। सरकार के पास इसका कोई अनुमान नहीं कि मेलों, सांस्कृतिक समारोहों व कुश्तियों के वार्षिक आयोजन में आय-व्यय का क्या हिसाब है। यही वजह है कि सियासत के दम पर केवल सत्ता का प्रभाव नेताओं की वकालत में हर वर्ष नया प्रचलन पैदा करता है।

निवेश सुविधा समझौते को रोकना कितना जायज

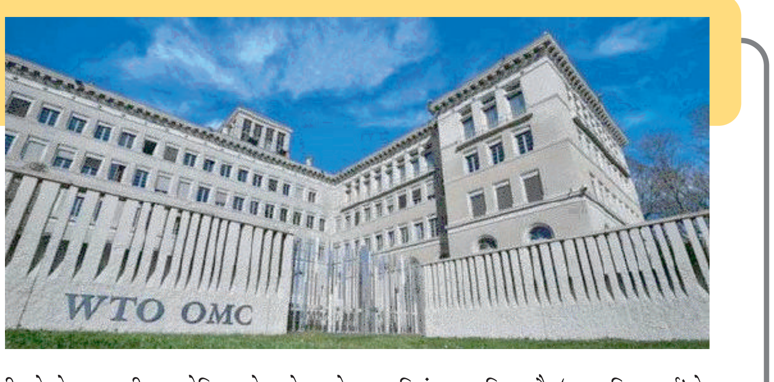

अपनी ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से चीन बीआरआई में भाग लेने वाले देशों से प्रमुख रणनीतिक संपत्ति और स्थान छीनने में सक्षम हो गया है। इसलिए इसे रोकने की जरूरत थी'

डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अभी संपन्न हुआ है जिसमें इस बात पर भारी उत्सुकता दिखी कि क्या डब्ल्यूटीओ में एक और प्लुरिलेटरल समझौता, यानी एक समझौता जिसमें डब्ल्यूटीओ के सभी देश नहीं, बल्कि कुछ ही देश शामिल होंगे, जिसका नाम है विकास के लिए निवेश सुविधा समझौता (आईएफएडी) शामिल हो पाएगा? गौरतलब है कि इस प्रस्तावित समझौते को 120 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त था, यानी इसमें विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता 70 प्रतिशत से अधिक देश शामिल थे। महत्वपूर्ण है कि डब्ल्यूटीओ एक बहुपक्षीय संगठन है, इसके अधिकांश समझौते प्रकृति में बहुपक्षीय रहे हैं, जिन्हें सभी सदस्य देशों ने मान्य किया। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के गठन से पहले भी 'गैट' के अंतर्गत प्लुरिलेटरल समझौते होने की मिसालें हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत प्लुरिलेटरल समझौतों की अनुमति है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में, बहुपक्षीय समझौते नियम हैं, जबकि प्लुरिलेटरल अपवाद हैं। आईएफएडी पर नाटक तब अचानक समाप्त हो गया जब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ में इस प्लुरिलेटरल समझौते की कानूनी अस्वीकार्यता के बारे में डब्ल्यूटीओ में 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया।

आईएफएडी क्या है : आईएफएडी विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तावित एक व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बनाना है। इसके लिए राज्यों को विनियामक पारदर्शिता और निवेश उपायों की पूर्वानुमेयता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय समझौता घरेलू नियमों के दायरे को सीमित करता है, आईएफएडी के मामले में यह स्थिति अधिक भयावह थी और निवेश सुविधा के नाम पर सदस्य देशों के संप्रभु अधिकारों की तिलांजलि दिए जाने का प्रावधान था।

आईएफएडी को लेकर भारत क्यों चिंतित था : आम तौर पर समझौते, चाहे प्लुरिलेटरल हों या बहुपक्षीय, तब बनते हैं जब देशों का एक समूह एक मान्य नियमावली पर सहमत होने के लिए इक_ा होता है, जिसका किसी मामले पर पालन किया जाएगा, और यह एक दूसरे के लिए पारस्परिक लाभ के लिए होता है। हालांकि आईएफएडी की खासियत यह है कि इस प्रस्तावित आईएफएडी को एक देश (चीन) ने अपने लाभ के लिए आगे बढ़ाया और एक प्रमुख सैन्य और आर्थिक शक्ति चीन द्वारा दबाव डालकर अन्य सदस्यों से आंख मूंद कर हस्ताक्षर करवाए गए। चीन का एकमात्र उद्देश्य आईएफएडी सदस्य देशों को अपने-अपने देशों में निवेश की सुविधा के लिए मजबूर करके अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित समझौता सदस्य देशों को अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, मानक प्रथाओं को शुरू करने और नौकरशाही बाधाओं से बचकर किसी भी विदेशी इकाई द्वारा निवेश की सुविधा प्रदान करने का आदेश देता है। यह समझ में आता है कि पिछले एक दशक में चीन, विकासशील और यहां तक कि कुछ विकसित देशों को चीन द्वारा ही बनाई जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उदार वित्तपोषण का लालच देकर ऋण जाल में धकेलने के अपने विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान में बेल्ट रोड पहल की आड़ में चीन की ऋण जाल कूटनीति के कारण कई देश पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी देशों को चीन पहले ही अपनी इस कर्ज जाल कूटनीति से बर्बाद कर चुका है। प्रस्तावित समझौते से चीन को लूट, डकैती और अधीनता के लिए नए चारागाह प्राप्त करने में आसानी होती। बीआरआई के साथ चीन को एक नई विस्तारवादी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है।

आईएफएडी को कैसे रोका गया : चीन सहित कुछ वैश्विक शक्तियों के इशारे पर आईएफएडी को डब्ल्यूटीओ के दायरे में लाने के लिए डब्ल्यूटीओ सचिवालय की मदद से चीन का यह नापाक प्रयास वास्तव में पूरी तरह से अवैध था। अनुबंध 4 में बहुपक्षीय समझौते के रूप में आईएफएडी को जोडऩे की प्रक्रिया में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहले, प्रस्तावित आईएफएडी व्यापार समझौते के रूप में योग्य नहीं था। आईएफएडी में व्यापार से संबंधित कोई ठोस प्रावधान शामिल नहीं है, और इसलिए इसे व्यापार समझौते के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। दूसरा, आईएफएडी को डब्ल्यूटीओ में जोडऩे का अनुरोध केवल उन सदस्यों से ही आ सकता था, जिन्होंने आईएफएडी पर हस्ताक्षर करने और इसकी पुष्टि करने के लिए अपनी घरेलू प्रक्रियाओं को पूरा किया हो और जिनके लिए समझौता लागू हो गया है। तीसरा, आईएफएडी पर बातचीत बहुपक्षीय जनादेश के बिना शुरू की गई थी। यह सर्वसम्मति से निर्णय लेने की डब्ल्यूटीओ की लंबे समय से चली आ रही प्रथा के विपरीत था। इन सब कानूनी कमजोरियों के आलोक में, आईएफएडी को डब्ल्यूटीओ में एकीकृत करने का बहुचर्चित प्रस्ताव अचानक ध्वस्त हो गया।

चीन के नेतृत्व वाली इस कोशिश को आगे बढ़ाते समय नियम आधारित डब्ल्यूटीओ स्वयं भी अपने नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता। हम आगे देखते हैं कि आईएफएडी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो विकासशील देशों को विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद कर सके। वास्तव में यह विदेशी निवेशकों (यानी चीन) के हितों की रक्षा के लिए एक चार्टर था। यह बहुराष्ट्रीय निगमों को उन नए कानूनों के खिलाफ पैरवी करने के लिए मजबूत करता है जिनका वे विरोध करते हैं, जिससे उन्हें वे अधिकार मिलते हैं जो एक नागरिक के रूप में हमारे पास नहीं हैं। इसके अलावा, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करना एक संप्रभु या अन्य शब्दों में संप्रभु राष्ट्र के लोगों का विशेषाधिकार है, जिसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा कमजोर या कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। प्रस्तावित समझौते की विषय वस्तु और संरचना के पीछे भयावह मंसूबे की मंशा प्रतीत होती है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि निवेश सुविधा उपायों के लिए वैश्विक मानक बनाने की आड़ में, वे संप्रभु देशों को अपने संबंधित क्षेत्रों में एफडीआई को विनियमित करने और निगरानी करने के अधिकारों से वंचित करना चाहते थे। इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है कि डोकलाम के बाद भारत ने उन सभी देशों से जिनकी भारत के साथ साझा सीमा है, पर एफडीआई पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए, और 'स्वचालित मार्ग' के स्थान पर 'अनुमोदन मार्ग' के माध्यम से निवेश की अनुमति को अनिवार्य कर दिया। इस उपाय से, भारत ऐसे देश से निवेश को प्रतिबंधित कर सकता है जो भारत के साथ युद्ध में है।

यदि हम इस समझौते की अनुमति देते हैं, तो देश अपने-अपने हितों की रक्षा करने की ऐसी किसी भी स्वतंत्रता से वंचित हो जाएंगे। यह देखा जा रहा है कि आईएफएडी पर चीन ने दबाव डाला और बेल्ट रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में भाग लेने वाले छोटे देशों की बांह मरोडक़र प्रस्ताव पर सहमति देने वाले अधिक से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। अगर हम देखें, तो शुरुआत में आईएफएडी का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका को भी बाद में भारत के साथ अपने संयुक्त बयान से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कोई रहस्य नहीं है कि बेल्ट रोड पहल के माध्यम से चीन अपनी विस्तारवादी रणनीति के साथ अपनी कुटिल ऋण जाल कूटनीति को प्रभावी बना रहा है। अपनी ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से चीन बीआरआई में भाग लेने वाले देशों से प्रमुख रणनीतिक संपत्ति और स्थान छीनने में सक्षम हो गया है और तेजी से वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए वैश्विक शांति के हित में आईएफएडी को किसी भी कीमत पर अवरुद्ध करने की आवश्यकता थी।

डा. अश्वनी महाजन

विज्ञान हमें कहां से कहां ले आया!

हम तो फिर भी कहेंगे और सब कहते हैं कि विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है पर बीमारी घटने के बजाय बढ़ कैसे रही है ?

हर घर में कोई ना कोई दवाई क्यों खा रहा है? नहीं पता न ?

मैं बताता हूँ, हुआ ये है कि हमारे रसोई की मूलभूत चीजों में बहुत मिलावट, गिरावट और घटियापन आ गया है।

कौन कौन सी हैं वो चीजें ?

1. नमक, 2. गुड़, 3. तेल, 4. घी, 5. दूध, 6. आटा, 7. पानी, 8. शक्कर

जी हाँ बस इन चीजों में सुधार कीजिये और 6 महीनो में फर्क देखिये।

1. सब से पहले समुंद्री नमक- आयोडीन नमक को बदल के सेंधा नमक (रॉक सॉल्ट) कर दीजिये, वो भी बड़े टुकड़े लाके घर में ही कूट लें और हाँ नमक केवल रसोई बनाते वक्त ही डालें। टेबल पे रख के भोजन के समय डालने की आदत छोड़ें।

2. गुड़ हमेशा डार्क चॉकलेट कलर का ही लायें।सफ़ेद गुड़ में मिलावट होती है।

.3. Refined oil के बदले घानी का फिल्टर तेल ही खायें, वो भी मुंगफली, तिल या सरसों; कोई अन्य नहीं।

4. घी असली वो है जो देसी गाय के दूध से दहीं, दहीं से मख्खन और मख्खन से बनता है। सीधे मलाई निकाल के या विदेशी गाय के दूध से जो बनता है, वो बटर आयल है, घी नहीं।

5. दूध पिओ तो केवल देसी गाय का, नहीं तो पिओगे ही नहीं तो कोई नुकसान नहीं है।

6. आटा हमेशा मोटा पिसवाओ और बिना चोकर निकले प्रयोग में लाओ। मैदा कभी ना खायें।

7. पानी हमेशा मटके का या गुनगुना ही पीओ। ठंडा फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना।

.8. चीनी सफ़ेद जहर है। उसकी जगह गुड़ ही खायें या शक्कर जो थोड़ी पीली होती है। बड़े टुकडों में मिलती है, उसे प्रयोग करें।

अब आप कहेंगे इतना कुछ कौन करेगा ? टाइम नहीं है, तो टेंसन नहीं लेने का, मस्त से जियो,

कुछ नहीं होता है।

तो दोस्तों, आस-पास के जो लोग गोलियां खा रहे हैं, वो भी ऐसा ही सोचते थे लेकिन

अब वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के चक्कर काटने में टाइम निकाल ही रहे हैं।

थोड़ा सा बदलाव और सेहत बना

किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं, यह पता लगाना मुश्किल क्यों, नीति आयोग ने बताई वजह

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने 2016 में किसानों की आय (doubling farmers income) को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। पिछले कुछ वर्षों में किसानों की आमदनी बढ़ी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि आय दोगुनी हुई है या नहीं। अब नीति आयोग ने बताया है कि किसानों की असल आमदनी पता लगाने में क्या दिक्कत हो रही है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसानों की आमदनी (Farmers Income) में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार के लक्ष्य के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी हो गई है या फिर नहीं।

अब नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बताया है कि किसानों की असल आय जानने में कहां मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि हम दरअसल यह नहीं पता लगा पा रहे कि किसानों को दूसरे सोर्सेज से कितनी आमदनी हो रही है।

रमेश चंद का दावा है कि किसान गैर-कृषि स्रोतों से अधिक कमाई कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारे पास अधिक डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम स्पष्ट तौर पर यह नहीं बता पा रहे कि उनकी आय दोगुनी हुई है या नहीं।

सरकार के पास 2018-19 के बाद से इस बात का डेटा नहीं है कि किसानों को अन्य स्रोतों से कितनी कमाई हो रही है। रमेश चंद ने कहा कि जब आप किसानों की आय की गणना करनी है, तो उनकी कमाई के हर पहलू की जानकारी होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने 2016 में किसानों की आय (doubling farmers' income) को 2022 तक दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था।

इसके लिए जरूरी रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनी थी। कमेटी ने सितंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने पैनल की सिफारिशों को स्वीकार किया और प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक 'अधिकार प्राप्त निकाय' (Empowered Body) की स्थापना की है।

रमेश चंद का कहना है कि सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य इसलिए रखा था, ताकि हम अपनी कोशिशों को तेज कर सकें। अब इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हमने टारगेट को हासिल किया या नहीं। लेकिन, दुर्भाग्य से हमारे पास जरूरी डेटा नहीं हैं।

'Train 18' कैसे बन गई वंदे भारत? क्या है इस सेमी हाईस्पीड ट्रेन की पूरी कहानी; सुविधाएं ऐसी की हवाई जहाज भी फेल!

5 फरवरी 2019 को वंदे भारत से सफर करने का सपना साकार हुआ। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर हैं। यह आत्मनिर्भरता आधुनिकता और यात्री सुविधाओं पर भारत के बढ़ते ध्यान का प्रतीक हैं। यह न सिर्फ भारत की तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं बल्कभविष्य की राह भी दिखाते हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 10 और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही देश में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 51 हो गई है। वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे की आन-बान और शान बन गई हैं। आज हर रेल यात्री की चाहत है कि उसे भी कम से कम एक बार इन ट्रेनों में यात्रा करने का मौका मिले। वंदे भारत ट्रेनें अपनी शुरुआत से ही लोगों को आकर्षित करती रही हैं। इन ट्रेनों में देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के सपने को साकार किया है। साथ ही इनमें मिलने वाली सुविधाएं भी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन क्या आप इन ट्रेनों के शुरू होने के पीछे की कहानी जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं।

कैसे हुई शुरुआत?

भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे व्यापक रेल नेटवर्क में से एक है। यूं तो भारतीय रेलवे के पास राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज गति वाली प्रीमियम ट्रेनें पहले से मौजूद थीं, लेकिन यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और तेज गति का अनुभव प्रदान करने के लिए एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में साल 2017 में रेलवे ने सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों के विकास की योजना बनाई। इसके लिए किसी विदेशी कंपनी से करार करने की बजाए स्वदेशी तकनीक पर ही जोर दिया गया और इसका जिम्मा सौंपा गया चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) को। 'मेक इन इंडिया' के तहत इस पर काम शुरू हुआ और केवल 18 महीनों में अपने अथक प्रयासों के बाद भारतीय इंजीनियरों और टेक्नीशियनों ने साल 2018 में इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार कर दिया, जिसका नाम 'ट्रेन 18' रखा गया। उसके बाद शुरू हुआ परीक्षणों का दौर। तमाम मापदंडों पर खरा उतरने के लिए इस ट्रेन को व्यापक परीक्षणों से गुजारा गया और सुनिश्चित किया गया कि यह भारतीय रेलवे ट्रैकों और परिस्थितियों के अनुकूल है।

वंदे भारत का पहला सफर

15 फरवरी 2019 को वंदे भारत से सफर करने का सपना साकार हुआ। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। इसकी स्पीड के साथ ही इसमें मिलने वाली सुविधाओं ने भी यात्रियों को खासा प्रभावित किया। पहले इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था, लेकिन लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद इसे बदलकर 'वंदे भारत' कर दिया गया। यह नाम 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को दर्शाता है। पहले सफल सफर के बाद से इन ट्रेनों में और भी फीचर जोड़े गए। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन कई महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ रही हैं, जिनमें दिल्ली-कटरा, मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं।

भविष्य की रफ़्तार

वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। यह आत्मनिर्भरता, आधुनिकता और यात्री सुविधाओं पर भारत के बढ़ते ध्यान का प्रतीक हैं। यह न सिर्फ भारत की तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं बल्कभविष्य की राह भी दिखाते हैं। वंदे भारत 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकती है, जो इसे भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक बनाती है। मौजूदा ट्रेनों की तुलना में इसकी यात्रा में समय भी कम लगता है।

इन खूबियों से लैस है वंदे भारत ट्रेन

- वंदे भारत ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती है।
- वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों के आराम का पूरा ख्याल रखा जाता है। सीटें बेहद आरामदायक, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन वाली सीटें और पर्याप्त लेग स्पेस मिलता है।
- वाई-फाई कनेक्टिविटी से लैस डिब्बों में ऑटोमैटिक दरवाजे लगे होते हैं। साथ ही, एलईडी डेस्टिनेशन बोर्ड, टच स्क्रीन कंट्रोल और वैक्यूम शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
- सुरक्षा के लिहाज से भी वंदे भारत ट्रेनों में कई सुविधाएं शामिल की गई हैं, जैसे कि स्लाइडिंग कैप्सूल डिजाइन, जो टक्कर की स्थिति में यात्रियों की रक्षा करता है। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं।
- हर सीट के नीचे मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं।

इनसाइड

E- commerce उद्योग में बढ़ेगी सात लाख गिग नौकरियां, फेस्टिव सीजन में बढ़ी अस्थायी कर्मचारियों की डिमांड

स्टाफिंग कंपनी टीमलीज सर्विसेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ई-कामर्स कंपनियों त्योहारी सीजन से पहले वार्षिक खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए कमर कस रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष त्योहारी सीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले गिग नौकरियों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।इससे संकेत मिलता है कि ई-कामर्स उद्योग परिदृश्य को लेकर काफी आशावादी है।

नई दिल्ली। साल 2023 की दूसरी छमाही में ई-कामर्स उद्योग में सात लाख गिग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। इसका कारण यह है कि कंपनियां त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही हैं।

त्योहारी सीजन में गिग नौकरियों की संख्या में होगी बढ़ोतरी

स्टाफिंग कंपनी टीमलीज सर्विसेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ई-कामर्स कंपनियों त्योहारी सीजन से पहले वार्षिक खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए कमर कस रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष त्योहारी सीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले गिग नौकरियों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई, इसका भारत के निर्यात पर कैसा रहेगा असर?

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई। विश्व व्यापार में सुस्ती और अनिश्चितता का दौर है। इसके बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात पिछले साल के समान स्तर पर रहेगा। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात 776 अरब डॉलर था। आइए जानते हैं पूरी खबर।

नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि वैश्विक व्यापार में मंदी और अनिश्चितताओं के बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात पिछले साल के समान स्तर पर रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसी उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को लागू कर रही है, जिनका जोर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं पर है। ऐसा करने से देश के व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसलिए हमारा व्यापार घाटा पिछले साल की तुलना में काफी कम रहेगा। गोयल ने एक साक्षात्कार में बताया, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि हम चालू वित्त वर्ष में मार्च के अंत तक पिछले साल के समान स्तर पर होंगे। हमारी वस्तुओं और सेवाओं के बीच कुछ समायोजन हो सकता है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम पिछले साल के समान स्तर पर होंगे।

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी के दौरान भारत का वस्तु निर्यात 4.89 प्रतिशत घटकर 353.92 अरब डालर था। इन दस महीने में सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 84.45 अरब डालर था।

पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात 776 अरब डॉलर था। रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ ही इजरायल-हमास संघर्ष के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हुई हैं। लाल सागर संकट के कारण परिवहन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार संकट से निपटने के लिए किसी प्रकार के समर्थन उपायों को बढ़ाने के बारे में सोच रही है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग वास्तव में ऐसा नहीं चाहता है कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पर निर्भर रहा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सेना और नौसेना के जरिये लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कर रही है।

सस्ता हुआ सोना लेकिन नहीं बदला चांदी का दाम, ऐसा रहा आज वायदा बाजार

परिवहन विशेष न्यूज

सोना-चांदी की नई कीमतें जारी हो गई हैं। वायदा कारोबार की ही बात करें तो आज सोने की कीमत में गिरावट दर्ज हुई है। वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत 75 रुपये गिरकर 65960 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत की बात करें तो वायदा कारोबार में आज चांदी की कीमत बिना बदलाव के अपडेट हुई।

नई दिल्ली। मंगलवार के कारोबारी दिन के लिए सोना-चांदी की नई कीमतें जारी हो गई हैं। 12 मार्च को सोने की कीमत में 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 66,350 रुपये हो गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक, सोने की कीमत में यह कमी ग्लोबल कारणों से देखने को मिली है। वहीं, चांदी की कीमत 400 रुपये की बढ़त 75,900 रुपये प्रतिकिलो पहुंच गई।वायदा कारोबार की ही बात करें तो आज सोने की कीमत में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं चांदी की कीमतें वायदा बाजार में स्थिर रहीं।

सोने की वायदा कीमत

वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत 75 रुपये गिरकर 65,960 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 75 रुपये या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65,960 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 17,503 लॉट का कारोबार हुआ।वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,183.20 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

चांदी की वायदा कीमत

मंगलवार को चांदी की कीमत 74,511 रुपये प्रति किलोग्राम पर ही रही। इस कीमत में

किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, मई डिलीवरी के लिए चांदी का अनुबंध 22,737 लॉट के कारोबार के साथ 74,511 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिना बदलाव के अपडेट हुआ।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24.65 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

लाल सागर में हाउती विद्रोहियों के हमले से ग्लोबल ट्रेड को बड़ा नुकसान, अगले वित्त वर्ष से दिखने लगेगा असर

परिवहन विशेष न्यूज

लाल सागर व्यापार को लेकर आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई (GTRI) ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार लाल सागर के संकट का असर आने वाले वित्त वर्ष में भी देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों को उद्योगों में सबसे अधिक व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस संकट का असर भारतीय व्यापार पर भी पड़ रहा है।

नई दिल्ली। लाल सागर व्यापार को लेकर आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई (GTRI) की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर दिन बढ़ते हमलों का अंत नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में इसका असर लाल सागर व्यापार पर देखने को मिल रहा है।

लाल सागर संकट पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। यह संकट तब शुरू हुआ जब यमन में ईरान समर्थित हाउथी आंदोलन ने यमनी तट के पास जहाजों पर हमला शुरू किया।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कहा कि बढ़ती शिपिंग, और बीमा लागत और शिपमेंट के लेट होने से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं बाधित होंगी। दरअसल, लाल सागर संकट की वजह से मार्जिन कम होगा और मौजूदा स्थानों से कई कम-मार्जिन वाले उत्पादों का निर्यात अव्यवहारिक हो जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को उद्योगों में सबसे अधिक व्यवधान का सामना करना पड़ेगा।

लाल सागर व्यापार से हो रही परेशानी का असर भारतीय व्यापार, खासकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के साथ व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। भारत, कच्चे तेल और एलएनजी आयात और प्रमुख क्षेत्रों के साथ व्यापार के लिए बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य (Bab-el-Mandeb Strait) पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी व्यवधान से पर्याप्त आर्थिक और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

वित्त वर्ष 2023 में भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 65 प्रतिशत, जिसका मूल्य 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इराक, सऊदी अरब और अन्य देशों से आया है।

रिपोर्ट के अनुसार यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ कुल व्यापारिक व्यापार के लिए लाल सागर का लगभग 50 प्रतिशत आयात और 60 प्रतिशत निर्यात यानी कि कुल मिलाकर 113 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजमर्रा के बढ़ते हमलों और कोई अंत नजर नहीं आने के कारण, लाल सागर संकट 2024 में व्यापार की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस संघर्ष के कारण शिपिंग लागत में वृद्धि (40-60 प्रतिशत) और मार्ग परिवर्तन (20 दिन अधिक तक), उच्च बीमा प्रीमियम (15-20 प्रतिशत), और चोरी और हमलों से संभावित कार्गो हानि के कारण देरी हो रही है।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कन्फेक्शनरी कंपनियों को कोको की ऊंची कीमतों और

अफ्रीका से देर से डिलीवरी के कारण कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मुनाफा कम हो रहा है। कपड़ा और चमड़ा उद्योग, जो कम मार्जिन पर काम करते हैं, खरीदारों के साथ शिपिंग लागत पर फिर से बातचीत कर रहे हैं, जिससे कमाई प्रभावित हो रही है। कार निर्माता अलग-अलग शिपिंग पथों का उपयोग कर रहे हैं।

लाल सागर संकट के बारे में

लाल सागर संकट बड़े पैमाने पर 19 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुआ। यह तब शुरू हुआ जब यमन में ईरान समर्थित हाउथी आंदोलन ने यमनी तट के पास नागरिक-संचालित मालवाहक जहाजों पर हमले शुरू किए। हाउती ने ऐसे किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया है जो इजराइल से जुड़ा हुआ माना जाता है, हालांकि जिन जहाजों पर हमला किया गया उनका इजराइल से कोई स्पष्ट संबंध नहीं था।

रिपोर्ट के अनुसार यह स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान, हमास और इजराइल से जुड़े एक व्यापक छद्म संघर्ष का हिस्सा है। मार्च 2024 में संकट अपने पांचवें महीने में था।

ECI: आयोग ने किया चुनाव चिह्न आदेश 1968 में संशोधन; आम चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के लिए उठाया ये बड़ा कदम

परिवहन विशेष न्यूज

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 में संशोधन को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। आयोग ने इस अधिसूचना में बताया कि संशोधित कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

नई दिल्ली। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। इस बीच, चुनाव आयोग ने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 में बड़ा संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद चुनाव निशान के आवंटन से जुडे कानून को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया है।

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 में संशोधन को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। आयोग ने इस अधिसूचना में बताया कि संशोधित कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि पार्टी के चुनाव निशान से जुडे नियम में यह संशोधन इसलिए किया गया है ताकि इसे जम्मू-कश्मीर में लागू किया जा सके। इस आदेश में राजनैतिक दलों के लिए चुनाव निशान का आवंटन, निशान आरक्षण और अंतर-पार्टी विवादों को हल करने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

गौरतलब है कि जब तक जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान लागू थे, तब तक वहां चुनाव से संबंधित भारत के नियम लागू नहीं होते थे। बाद में जब साल 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द कर दिया गया और राज्य को केंद्र-शासित प्रदेश में बांट दिया गया तब वहां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान लागू हो गए।

पहले के आदेश में कहा गया था कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधान पूरे भारत में लागू थे। बस यह जम्मू-कश्मीर राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में लागू नहीं था। अब संशोधित नियम में बताया गया है कि चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश अब पूरे भारत में सभी संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों के संबंध में लागू होता है। पहले के आदेश में 'राज्य' शब्द में केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को शामिल किया गया था। वहीं संशोधन के बाद इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को भी शामिल किया गया है। बता दें कि देश में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा का प्रावधान है।

द्वारका एक्सप्रेस-वे से गुरुग्राम को आर्थिक तौर पर मिलेगी मजबूती, संपत्तियों में होगा इजाफा

द्वारका एक्सप्रेस-वे पर लोग लंबे समय से कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे थे। इसके शुरू होने के बाद वर्तमान आवंटी तो शिफ्ट करेंगे ही और साथ ही कनेक्टिविटी के इंतजार में नए आवंटी भी अब आशियाने खरीद सपनों को पूरा करेंगे। यहीं नहीं इससे अब रीसेल की संपत्तियों में 10-15 प्रतिशत तक का इजाफा देखने को मिलेगा।

परिवहन विशेष न्यूज

नया गुरुग्राम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सोमवार को गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के बाद रियल एस्टेट मार्केट में उछाल और तेजी तय मानी जा रही है। इसके शुभारंभ से निश्चित ही यहां रहने वाले लाखों लोगों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा और यह एक्सप्रेस-वे अब हजारों लोगों को यहां पर निवेश के लिए भी आकर्षित करेगा।

मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

रियल एस्टेट एक्सपर्ट एवं होमेंटस रिसर्च एंड एनेलिसस कंपनी के संस्थापक प्रदीप मिश्रा की माने तो, द्वारका एक्सप्रेस-वे पर लोग लंबे समय से कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे थे, काफी लोग तो कनेक्टिविटी से चलते अपने आशियानों में शिफ्ट भी नहीं हो रहे थे, लेकिन इसके शुरू होने के बाद वर्तमान आवंटी तो शिफ्ट करेंगे ही और साथ ही कनेक्टिविटी के इंतजार में नए आवंटी भी अब आशियाने खरीद सपनों को पूरा करेंगे।

यहीं नहीं इससे अब रीसेल की संपत्तियों में 10-15 प्रतिशत तक का इजाफा देखने को मिलेगा। एक अन्य एक्सपर्ट के अनुसार मार्केट रेट की बात करें 2020 में फ्लैटों की मूल बुकिंग सात से आठ हजार रुपये प्रति वर्ग फीट थी, 2021 में 8500, 2022 में दस हजार, 2023 में 15-16 हजार और 2024 में अब यह मार्केट 18 से 21 हजार के करीब पहुंच गई है।

दिल्ली आना-जाना होगा आसान

जीएलएस ग्रुप के निदेशक सुरिंदर सिंह का कहना है कि अब तक कनेक्टिविटी के चलते दिल्ली से लोग यहां नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब कनेक्टिविटी होने से आवाजाही बढ़ेगी। साथ ही निवेश में भी नये आयाम स्थापित होंगे। मिलेनियम सिटी के लिए द्वारका एक्सप्रेस-वे विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। स्टेट-आफ-आर्ट परियोजना में आधुनिक आठ-लेन एक्सप्रेसवे अनूठा उदाहरण है जो दिल्ली और गुरुग्राम के प्रमुख स्थानों को जोड़ता है और गुरुग्राम के प्रापर्टी मार्केट और रियल एस्टेट क्षेत्र के परिदृश्य को नया आकार देता है।

प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक एवं चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड बेहतर कनेक्टिविटी से द्वारका एक्सप्रेस-वे पर लग्जरी हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी और प्राप्टी की कीमतों में भी इजाफा होगा। द्वारका एक्सप्रेस-वे की शुरुआत यहां रहने वाले और निवेश करने वाले दोनों प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। *-नवदीप सरदाना, सीएमडी, व्हाइटलैंड कोरपोरेशन*

फरीदाबाद, एसपीआर, एनपीआर, सीपीआर, मुंबई एक्सप्रेस-वे, द्वारा एक्सप्रेस-वे से एयरपोर्ट और दिल्ली के आस-पास शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी गुरुग्राम रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। - *अमित गुप्ता, एमडी, ओरिस ग्रुप*

द्वारका एक्सप्रेस-वे गुरुग्राम के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। इसके शुभारंभ होने से डेवलपर्स, निवेशकों और आवंटियों के लिए रियल एस्टेट में नये रास्ते खुलेंगे। देश के प्रधानमंत्री द्वारा गुरुग्राम को ढांचागत विकास के तौर पर समर्पित द्वारका एक्सप्रेस-वे एक अमूल्य उपहार है। ***नरेंद्र यादव, अध्यक्ष, गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन***

टिकट न मिलने से नाराज अर्जुन सिंह ने दिए BJP में शामिल होने के संकेत

परिवहन विशेष न्यूज

भाजपा में शामिल होने का संकेत देते हुए अर्जुन सिंह ने अपने कार्यालय से टीएमसी सुप्रीमो और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें हटा दी। इतना ही नहीं उनकी जगह पीएम मोदी की तस्वीरें लगा दी।

दो साल पहले भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए अर्जुन सिंह ने दोबारा भाजपा में शामिल होंने के संकेत दिए हैं। बैरकपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टीएमसी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने सीएए के नियमों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ भी की है। जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि अर्जुन सिंह दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

भाजपा में शामिल होने के संकेत देते हुए सांसद अर्जुन सिंह ने बैरकपुर से टिकट न मिलने पर कहा कि पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। इस दौरान उन्होंने बैरकपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार पार्थ भौमिक के खिलाफ चुनाव लड़ने की कसम खाई। सिंह ने कहा कि वे उन लोगों को निराश नहीं कर सकते, जिन्होंने 2019 में चुनकर उन्हें लोकसभा में भेजा था। अर्जुन सिंह ने सीएए को लेकर ममता बनर्जी के राजनीतिक रुख पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के सपनों को पूरा करने और उन्हें नागरिकता का अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे ऐतिहासिक फैसले का विरोध कर रहे हैं वे राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं।

कार्यालय में लगाई पीएम मोदी की तस्वीर

वहीं, भाजपा में शामिल होने का संकेत देते हुए अर्जुन सिंह ने अपने कार्यालय से टीएमसी सुप्रीमो और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें हटा दी। इतना ही नहीं उनकी जगह पीएम मोदी की तस्वीरें लगा दी।

हो सकती है भाजपा में वापसी

अर्जुन सिंह बैरकपुर से भाजपा सांसद हैं। वह 2019 में टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए थे, और सांसद बने थे। इसके बाद साल 2022 में वे भाजपा छोड़कर दोबारा टीएमसी में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को ज़िला कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ज़िला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिए कि समन्वय के साथ सार्वजनिक सेवाओं को सुगमता से संचालित करें। जिला कलक्टर शेखावत ने विभागवार समीक्षा कर निर्देश दिये कि राज्य सरकार की सौ दिवसीय कार्ययोजना के तहत लंबित बिंदुओं को शीघ्रता से निस्तारित करें।

ज़िला कलेक्टर शेखावत ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ कर परिवादियों की संतुष्टि स्तर के प्रतिशत में वृद्धि करें।

चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, पेयजल सहित आमजन से सीधे जुड़े विभागों की सेवाएं सुचारू रखने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने जेवीवीएनएल अधीक्षण अभियंता को कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू कनेक्शन, बकाया बिलों, बिजली छीजत, के बारे में जानकारी ली तथा गर्मियों के समय सुचारू बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए एवं बकाया चल रहे बिजली के बिलों की रिकवरी करने के निर्देश भी दिये। ज़िला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर को नालों की सफाई करने, पूरे शहर में व्यवस्थित कचरा पात्र रखवाने, शहर का आकर्षक सोंदरीकरण करवाने तथा ज़िले में स्टेडियम एवं ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए भूमि चयन करने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में ज़िला कलेक्टर ने आगामी फूल डोल मेले की तैयारियो के संबंध में भी सभी संबंधित अधिकारियो को प्रभावी दिशा निर्देश प्रदान किए। डीओआइटी सायुक्त निदेशकविजय कुमार को जिले में नवीन पदस्थापित जिला स्तरीय अधिकारियों की आईडी मैप करने, ई राज-काज मोबाइल ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी सभी अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जिससे सभी फाइलों का निस्तारण ऑनलाइन ही सरलता से किया जा सके। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता से विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली तथा सभी रास्तों को रिकॉर्डेड करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर शेखावत ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जनसुनवाई के प्रकरणों को उसी स्तर पर समाधान करने, कार्यालय को समय पर खोलने तथा हमेशा जनसुनवाई करने, सीएमओ तथा विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों के लिए अलग से रजिस्टर खोलने तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर प्रकरणों को यथा समय समाधान करने के निर्देश प्रदान किए। बैठक के दौरान ज़िला पुलिस अधीक्षक राजेश कावट, उपखण्ड अधिकारी निर्मा विष्णोई सहित संबंधित ज़िला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एच.एस.आर लेआउट वडेर में ध्वजारोहण कार्यक्रम सम्पन्न

जयकारों के बीच मंदिर के शिखर पर चढ़ाई ध्वजा

बेंगलूरू। सीरवी समाज ट्रस्ट एच.एस.आर लेआउट श्री आईमाताजी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं सीरवी समाज भवन के उद्घाटन की पंचम वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रातः मंदिर में पूजा-अर्चना की गई। उसके बाद अमर ध्वजा के लाभार्थी शोभाराम चोयल, प्रदीप, घनश्याम सोयल परिवार एवं बाबूलाल काग, राजूराम चोयल, मनोज कुमार, मुलेवा, तेजाराम देवड़ा परिवार ने आईमाता मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद महाआरती की गई। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष भुडाराम हाम्बड़, उपाध्यक्ष मांगीलाल चोयल, सचिव लक्ष्मणराम आगलेचा, सहसचिव केनाराम मुलेवा, सहसचिव छैलाराम काग, सहकोषाध्यक्ष बाबुलाल सोलंकी, कार्यकारिणी सदस्य नेमाराम परिहारीया, नारायण लाल सोलंकी, चेनाराम राठौड़, गेनाराम सैणचा, मांगीलाल सोलंकी, ताराराम राठौड़, बगदाराम बर्फा, थानाराम काग, समस्त कार्यकारिणी सदस्य नवयुवक मंडल अध्यक्ष महेंद्र राठौड़, सचिव मदनलाल राठौड़ एवं समस्त कार्यकारिणी नवयुवक मंडल, महिला मंडल, गेर मंडल सदस्य उपस्थित रहे। सचिव लक्ष्मणराम आगलेचा के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम का समापन हुआ।

बीबीकेडीएवी कॉलेज फॉर वुमेन में 'पंजाबी भाषा और नैतिक मूल्यों' पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया,

अमृतसर (साहिल बेरी) बी। बी। के। डी। ए वी कॉलेज फॉर वूमेन, अमृतसर के स्नातकोत्तर पंजाबी विभाग ने विश्व भाषा दिवस को समर्पित 'पंजाबी भाषा और नैतिक मूल्यों' पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। इस समय माननीय एस. जगत पंजाबी सभा कनाडा के चेयरमैन अजायब सिंह चट्ठा मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। उनकी पत्नी श्रीमती बलविंदर कौर चट्ठा भी उनके साथ शामिल हुईं। एस। अरविंदर सिंह ढिल्लों, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, जिला प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान, नाभा, मुख्य अतिथि थे। श्री सुदर्शन कपूर, अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंधन समिति एवं प्राचार्य डॉ. पुष्पिंदर वालिया ने अतिथियों का छोटे पौधे देकर स्वागत किया।

मोहन मांझी के घर पर बीजेपी विधायकों की बैठक

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर्: राज्य में जहां बिजेड़ी और बीजेपी के बीच तनातनी चल रही है, वहीं आज बीजेपी विधायक मोहन माझी के घर पर पार्टी विधायकों की बैठक चल रही है। राजनीतिक माहौल गरमा गया है। राज्यपाल रघुवर दास ने दिल्ली जाकर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली में डेरा डाला, विधायकों के जमावड़े को लेकर खूब चर्चा हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, आज शाम बीजेपी विधायक पार्टी के मुख्य सचिव मोहन माझी के भुवनेश्वर स्थित सरकारी आवास पर पार्टी के कुछ विधायकों की मुलाकात हुई है। बिधायक कुसुम टेटे, बुधन मुर्मू, भास्कर मढेई और नारायण राव प्रमुख हैं। यह पता नहीं चल पाया है कि ये विधायक क्यों एकजुट हुए हैं और किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन बीजेपी विधायकों की इस मुलाकात को बीजेपी के साथ मेंट चोरक के राजनीतिक हलकों में काफी अहमियत दी जा रही है। अफवाह यह है कि राज्य में ऐसे कई विधायक और नेता नहीं हैं जो बिजेड़ी और गठबंधन के पक्ष में हों। वे लगातार इस संभावित विलय का विरोध करते रहे हैं। अफवाह यह है कि संभावित विलय के विरोध में पार्टी विधायक आज मोहन माझी के घर पर बैठक कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अब विधायकों की ओर कई नेताओं का सस्पेंस बढ़ा दिया है।

अमृतसर के विकास में भारत-अमेरिका साझेदारी का उपयोग करना चाहते हैं तरनजीत सिंह संधू

भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते सबसे अहम: संधू

अमृतसर (साहिल बेरी) अमेरिका में राजदूत रहे सरदार तरनजीत सिंह संधू अमेरिका के साथ संबंधों का उपयोग अमृतसर के विकास में साझेदारी के लिए करना चाहते हैं। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद वह पिछले एक महीने से अपने गृह क्षेत्र अमृतसर में हैं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिल रहे हैं ताकि उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और उन्हें अपने व्यापार, शिल्प, कौशल और उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

प्रो सरचंद सिंह ने कहा कि राजदूत संधू, हालांकि खुले तौर पर मुख्यधारा की राजनीति में अपनी भागीदारी व्यक्त करने में अनिच्छुक हैं, लेकिन अमृतसर लोकसभा सीट के लिए भाजपा के सबसे मजबूत और संभावित उम्मीदवार हैं। उन्होंने आज एक अंग्रेजी अखबार से भारत-अमेरिका संबंधों और अमृतसर में वे जो बदलाव लाना चाहते हैं, उस पर भी बात की। उन्होंने बिडेन प्रशासन के तहत भारत-अमेरिका संबंधों के सर्वकालिक उच्च स्तर पर होने का सारा श्रेय दोनों नेताओं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ-साथ राज्य सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित उनकी टीमों को दिया। जिसका वो भी हिस्सा थे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं. राजदूत संधू ने कहा कि यह अमेरिका के साथ-साथ भारत के लिए भी चुनावी साल है. अगर अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो भी इसका मौजूदा रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के समर्थन से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते द्विपक्षीय हो गए हैं. यह बिडेन और ट्रम्प दोनों के भारत के प्रति दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। साझेदारी हमेशा फलदायी रहेगी और अमेरिका का फोकस भारत पर रहेगा. राजदूत बनने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में पूछे जाने पर, राजदूत संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका ने एक-दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसे को आधार बनाया है, जो रिश्ता कभी एक रिश्ता था वह अब साझेदारी या पार्टनरशिप में बदल गया है। इसका असर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में देखा जा सकता है. यह सिर्फ औपचारिक पहलू नहीं था. क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने तीन दिनों के लिए व्हाइट हाउस में मोदी का स्वागत किया. दूसरा, जैसे-जैसे संबंध साझेदारी में बदलता है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्रों में सहयोग है, जिसमें आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल, प्रौद्योगिकी कौशल, साथ ही क्रिटिकल और इमेजिंग टेक्नोलॉजी (आईसीईटी) पर पहल शामिल है। एक सहयोगी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया था इसके अलावा Google, Microsoft, Apple, IBM ने भारत में निवेश की घोषणा की है। यूक्रेन पर कथित परमाणु हमले पर रूस के रुख को नरम करने का श्रेय मोदी को दिए जाने पर सीएनएन की एक रिपोर्ट का हवाला देते पर संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बिडेन ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुरक्षित करने पर काम किया है, जिसके बारे में दस्तावेज मौजूद हैं। यह बात सबसे पहले 2022 में CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने कही थी.

भारत लौटने के बाद वह एक महीने से अमृतसर में रह रहे हैं। क्या इसे मुख्यधारा की राजनीति में आपके प्रवेश के रूप में देखा जा सकता है पर सरदार संधू ने कहा कि अमृतसर उनका घर है. मेरा शहर से गहरा नाता है और मैं अमेरिका के साथ भारत के सहयोग का लाभ अमृतसर लाना चाहता हूं। मैं शहर के विकास में योगदान देना चाहता हूं।' मैं एक महीने से अधिक समय से यहां हूं और हर किसी को अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग की अपार संभावनाओं के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अमृतसर के युवा हर तरह से सक्षम हैं और मैं उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए छोटे दायरे से बाहर सोचने की सुविधा देना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने किन्नू जैसे फलों को यूरोप या पश्चिम एशिया में निर्यात किया होता, तो उन्हें 15 गुना अधिक कमाई होती। इसके अलावा, यह कई युवाओं को अवैध मार्गों से पश्चिम जाने पर विचार करने से रोकेगा। इसके अलावा निर्यात में ऐसे प्रयासों से एमएसपी का मुद्दा अप्रासंगिक हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के साथ अपने संबंधों का उपयोग अमृतसर में साझेदारी के लिए करना चाहता हूं. हर दिन एक लाख से अधिक पर्यटक अमृतसर आते हैं, मुख्य रूप से स्वर्ण मंदिर और दुर्गयाना मंदिर, जलियांवाला बाग और अटारी देखने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि राम तीर्थ नामक एक स्थान है जहां लव और कुश (राम और सीता के पुत्र) का जन्म हुआ था। यह स्थान पर्यटन मानचित्र पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वॉल-मार्ट जैसे स्टोर्स से फुलकारी से लेकर पंजाबी जूतों तक, पंजाबी हस्तशिल्प को आसानी से प्रमोट किया जा सकता है। जिससे निर्माताओं को भारी मुनाफा मिल सकेगा.

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023